



संदर्भ सं. राबे.पुनर्वित्त विभाग/2110-2115/ जीएसएस-एएमआई/2018-19

परिपत्र सं. 283 / पुनर्वित्त विभाग 68 / 2018-19

26 नवंबर 2018

प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अध्यक्ष
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
राज्य सहकारी बैंक
राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
नैबकिसान

महोदय

**एकीकृत कृषि आधारभूत संरचना योजना
(आईएसएएम) की उपयोजना 'कृषि विपणन
आधारभूत सुविधा' (एएमआई) योजना -
परिचालनात्मक दिशानिर्देश**

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 05 नवंबर 2018 के अपने पत्र संदर्भ सं. 19012/1/2018/ एम-II के माध्यम से एकीकृत कृषि आधारभूत संरचना योजना (आईएसएएम) की नयी उपयोजना 'कृषि विपणन आधारभूत सुविधा' (एएमआई) के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं. यह योजना विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) के माध्यम से कृषि, सहकारिता और

**New Agricultural Marketing
Infrastructure (AMI) sub-
scheme of Integrated Scheme
for Agricultural Marketing
(ISAM) -
Operational Guidelines**

Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, GoI vide their letter Ref. No. 19012/1/2018/M-II dated 5 November 2018 have issued the operational guidelines for the new Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) sub-scheme of Integrated Scheme for Agricultural marketing (ISAM). The scheme will be implemented by the Department

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 • टेलि. : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department Of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel. : 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार कार्यान्वित करेगा.

2. पूर्व में 01 अप्रैल 2001 से लागू की गई तत्कालीन ग्रामीण भंडारण योजना (जीबीवाई) और 20 अक्टूबर 2004 से लागू कृषि विपणन आधारभूत संरचना विकास/ सुदृढीकरण, ग्रेडिंग और स्टैंडरडाइजेशन (एएमआईजीएस) को 01 अप्रैल 2014 से एकीकृत कृषि विपणन योजना के कृषि विपणन आधारभूत संरचना उपयोजना में विलय किया गया था. कृषि विपणन आधारभूत संरचना योजना XIIवीं योजना (2012-17) के लिए थी और तत-उपरांत यह योजना बंद कर दी गई थी.

3. 14वें वित्त आयोग की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए नई योजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन 22 अक्टूबर 2018 से किया गया. तदनुसार, वित्तीय संस्थाओं द्वारा 22 अक्टूबर 2018 को या इसके बाद 31 मार्च 2020 तक मीयादी ऋण युक्त परियोजनाएँ जो कृषि विपणन आधारभूत संरचना (एएमआई) उपयोजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी हैं, पर संशोधित दिशानिर्देश प्रभावी होंगे. नई योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देश संलग्न हैं.

4. एएमआई उपयोजना आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण के माध्यम से ग्राम (ग्रामीण कृषि बाज़ार) के रूप में ग्रामीण हाट के विकास और उन्नयन पर विशेष बल देती है. ये ग्राम (GrAM), किसान उत्पादक संगठन और अन्य योग्य प्रमोटरो की भागीदारी के साथ माध्यमिक बाज़ार (हब) के

of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare, GoI through the Directorate of Marketing & Inspection (DMI).

2. The erstwhile Grameen Bhandaran Yojana (GBY) implemented since 01.04.2001 and Scheme for Development/ Strengthening of AMI, Grading & Standardisation (AMIGS) implemented since 20.10.2004 were subsumed into AMI sub-scheme of ISAM since 01.04.2014. The AMI scheme was for XII Plan (2012-17) and the scheme was discontinued.

3. The new scheme has been approved for implementation from 22 October 2018 for the period conterminous with the 14th Finance Commission i.e. upto 31 March 2020. Accordingly, the revised guidelines for the sub-scheme AMI will be effective for new credit linked projects for which term loan is sanctioned by the FIs on after 22 October 2018 to 31.03.2020. The operational guidelines for the new scheme are enclosed.

4. The sub-scheme AMI lays special focus on developing and upgrading of Gramin Haats as GrAMs through strengthening of infrastructure. These GrAMs may function as farmer-consumer market (retail market) and collection/aggregation points (spokes) with linkages to secondary

संबंध में किसान उपभोक्ता बाज़ार (खुदरा बाज़ार) और संग्रह/एकत्रीकरण बिन्दु (स्पोक्स) के रूप में कार्य कर सकते हैं. योजना में मुख्यतः किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है.

5. इस एएमआई योजना में पात्र भंडारण और विपणन आधारभूत संरचनाओं में ऋण युक्त निवेश के लिए बैंक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान है. क्षेत्र और लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर पात्र सब्सिडी पूंजीगत लागत का 25% या 33.33% होगी.

6. नाबार्ड योजना के अंतर्गत नाबार्ड पुनर्वित्त के लिए पात्र सभी संस्थाओं और इस प्रयोजना के लिए अन्य ऐसी संस्थाओं जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो, को सब्सिडी जारी करेगा. यह भी ध्यान दिया जाए कि दिशानिर्देशों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दस्तावेजों की प्रस्तुति से लेकर अंतिम सब्सिडी जारी करने तक के लिए प्रत्येक चरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है. वित्तीय संस्थाओं पर अंतिम सब्सिडी की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

7. नाबार्ड वर्तमान नीति के अनुसार वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों, पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम (एनईडीएफआई) आदि को पुनर्वित्त भी प्रदान करेगा. पुनर्वित्त पर ब्याज की दर नाबार्ड द्वारा

market (hub) with participation of FPOs and other eligible promoters. Enhancement of farmers' income is central to the scheme.

5. The AMI scheme envisages back-ended capital subsidy for credit linked investment in eligible storage and marketing infrastructure projects. The eligible subsidy is 25% or 33.33% of the capital cost depending upon the area and category of beneficiary.

6. NABARD will release subsidy under the scheme to all the institutions which are eligible for NABARD refinance and to such other institutions GoI may approve for the purpose. It may be noted that time limits have been prescribed in the guidelines for each stage from submission of documents by FI to release of final subsidy. On receipt of subsidy by FI, the Utilization Certificate should be submitted by the FI within 60 days of receipt of final subsidy.

7. NABARD will also provide refinance to Commercial Banks, RRBs, StCBs, SCARDBs, Scheduled Urban Cooperative Banks, Scheduled Primary Cooperative Banks (PCBs), North Eastern Development Financial Corporation (NEDFi), etc., as per the extant policy. The rate of interest on refinance will be as decided by NABARD from time to time.

समय-समय पर निर्धारित की जाएगी. पुनर्वित्त प्रस्ताव वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किए जा सकते हैं.

8. बैंक योजना की आवश्यकताओं और परिचालनात्मक दिशानिर्देशों तथा अनुबंध X की विषय-वस्तु (जिसे स्वीकृति पत्र में संलग्न भी किया जाना है) के संबंध में उधारकर्ता का मार्गदर्शन करें.

9. नाबार्ड आवेदन संबंधी जानकारी की प्रस्तुति, इनकी जांच और सब्सिडी दावे जारी करने संबंधी सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया में है. यह 60 दिन के भीतर आरंभ किए जाने की अपेक्षा है. इस सॉफ्टवेयर के परिचालन संबंधी अनुदेशों की सूचना यथासमय दी जाएगी. इस बीच नए दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक रूप से आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं. सॉफ्टवेयर तैयार हो जाने के बाद आवश्यक जानकारी सिस्टम में दर्ज करनी होगी. योजना के डिजीटाइजेशन से न केवल यह प्रणाली दुरुस्त होगी बल्कि सब्सिडी जारी करने में पारदर्शिता भी आएगी.

10. इस योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देश हमारी वेबसाइट www.nabard.org पर भी उपलब्ध है.

11. कृपया इस योजना के कार्यान्वयन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश आप अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं में परिचालित करें. अनुरोध है कि इस योजना का, विशेषकर किसानों/ कृषक

Refinance proposals may be submitted as per existing procedure.

8. Banks may guide the borrower on the general requirements of the scheme as also on the contents of Annexure X to the operational guidelines (which is also to be attached to the sanction letter).

9. NABARD is in the process of developing a software for submission of application details, processing and release of subsidy claims. The same is expected to be operational within 60 days. The instructions for operating the software will be communicated in due course. In the interim, applications may be submitted in physical form to the Regional Offices of NABARD as per the formats prescribed in the new guidelines. Once the software is rolled out the relevant data will have to be entered in the system. Digitisation of the scheme processes will not only streamline the system but also infuse transparency in release of subsidy.

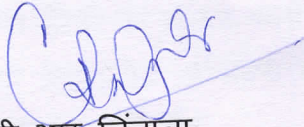
10. The operational guidelines of the scheme are also available on our website at www.nabard.org.

11. We request you to circulate the operational guidelines among your Controlling offices and branches for implementation. We

उत्पादक संगठनों/ कृषक उत्पादक कंपनियों और
भावी उद्यमियों में, व्यापक प्रचार प्रसार करें.

also request you to give wide
publicity to the scheme particularly
among farmers/FPOs/FPCs and
prospective entrepreneurs.

भवदीय



जी आर चिंताला
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोपरि



OPERATIONAL GUIDELINES 2018

AGRICULTURAL MARKETING INFRASTRUCTURE SUB-SCHEME OF INTEGRATED SCHEME FOR AGRICULTURAL MARKETING

(w.e.f. 22.10.2018 to 31.03.2020)

Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India

AGRICULTURAL MARKETING INFRASTRUCTURE (AMI)

1. INTRODUCTION

1.1 Agriculture is one of the most critical sectors of the Indian economy that not only drives the growth and development of agriculture and allied sectors directly but also affects the well-being of rural people at large, their prosperity and employment and also forms an important resource base for a number of agro-based industries and agro-services. While the food security constantly augmented through various plan periods by strategic planning and mission mode schemes has largely been achieved, but the fulcrum of monetising the farmers and their economic well being is still a challenge. Considering the aforesaid facts, there has been a major policy rejig from mere focussing food security to sustained income and nutritional security aligned climate change and gender equality. Conclusively, agriculture like any other enterprise can sustain, only when it can generate net positive returns to the producer. An efficient, competitive and accessible market with adequate post-harvest and marketing infrastructure can potentially achieve its core objective of generating net positive returns to the producer. In the light of the Government's vision to double farmers' income by 2022, it entails an urgent need for putting in place better farmer-market linkages through developing and upgrading Gramin Haats as Gramin Agricultural Markets (GrAMs) and declaring warehouses/cold storages as market sub-yards, promoting scales of economy in production & post-production activities through active participation of Farmer Producer Organizations, squeezing food supply chain through direct marketing in every forms of wholesale and retails (farmer-consumer market), symmetrising market information, promoting market driven production through a demand based market intelligence and price forecasting system and promoting quality management of farmers' produce. Further, by selling agri. and allied produce in more marketable and processed form by farmers themselves in the market may considerably enhance their income.

1.2 The scientific warehousing (godowning) in the marketing activity has multipronged role in reducing storages losses of all sort, functioning as market place, promoting pledge financing and also NWRS resultantly addressing the issue of distress sell and facilitating futures trading. Its utility is more so for small and marginal farming comprising more than 86 % of land holdings, which had been echoed in the 28th report of the Standing Committee on Agriculture. The estimates of National Centre for Agricultural Economics and Policy Research (NCAP) projecting total demand for food grains of the country to touch 281 million MT by 2020-21 further necessitates requirement for total storage capacity of around 196 million MT of marketable surplus.

1.3 The revitalized and farmers' income enhancing centric sub-scheme Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) of Integrated Scheme for Agricultural Marketing (ISAM) is meant for holistic development of agricultural value chain critically focussing each linkage of post-harvest value chain including promotion of value addition and processing at farmers level so as to enhance their income by selling more marketable and processed produce in

the market. The sub-scheme AMI lays special focus on developing and upgrading Gramin Haats as GrAMs through strengthening of infrastructure there for, which may function as farmer-consumer market (retails market) and collection/aggregation points (spokes) with linkage to secondary market (hub) and also to processing/ exporting and retain chain with participation of FPOs, other farmersøgroups and private sector eligible promoters . Farmer-consumer markets for agricultural and allied produce (livestock, fishery, poultry and such other allied produce) devoid of intermediaries and developed elsewhere also by eligible promoters will be focussed and eligible activity under this sub-scheme. Accordingly, this revised operational guidelines for the sub-scheme AMI are applicable for new credit linked projects, whose term loan by eligible financial institutions have been sanctioned on or after 22.10.2018 but not later than 31.03.2020, while in case of new own funded projects of state agency, which have been sanctioned by Project Sanctioning Committee (PSC) of DAC &FW on or after 22.10.2018 but not later than 31.03.2020.

1.4 The sub scheme on AMI will be implemented by the Directorate of Marketing & Inspection (DMI), an attached office of Department of Agriculture, Cooperation and farmers welfare. A list of Regional / Sub-Offices of DMI is at **Annexure-I**

2. OBJECTIVES OF THE SUB-SCHEME

2.1 Following are the major objectives:

2.1.1 To develop marketing infrastructure to effectively handle and manage marketable surpluses of agricultural and allied produce including horticulture livestock, poultry, fishery, bamboo, minor forest produce and such like produce supportive to enhance farmersøincome.

2.1.2 To promote innovative and latest technologies in post-harvest and agricultural marketing infrastructure.

2.1.3 To develop alternative & competitive marketing channels for agricultural and allied produce through incentivizing private and cooperative sectors to make investments there for.

2.1.4 To benefit the farmers individually and collectively through FPOs from farm level processing and marketing of processed produce along with promotion of small size processing units.

2.1.5 To promote creation of scientific storage capacity for storing farm produce, processed farm produce and agricultural inputs etc. to reduce post-harvest & handling losses, promote pledge financing and market access.

2.1.6 To incentivize developing and upgrading of Gramin Haats as GrAMs to make better farmer-consumer market linkages and also to assist in integration GrAMs with e-NAM portal so as to improve transparency in trading and better price discovery.

2.1.7 To provide infrastructure facilities for grading, standardization and quality certification of agricultural and allied produce with the objectives of (a) ensuring produce quality based value realization to farmers ; and (b) promoting pledge financing , e-NWRS and futures trading .

2.1.8 To promote Integrated Value Chains through minimal processing /value addition to make the produce more marketable , which includes washing, sorting, cleaning, grading, waxing, ripening, packaging, labelling etc., wherein the product form is not changed.

2.1.9 To undertake publicity and awareness campaign among the stakeholders including farmers, agri.preneurs, market functionaries of sub-scheme and on other various aspects and functions of agricultural marketing including grading, standardization, quality certification, regulation, reforms , e-trading, promoting farmers facilitation centre for market information & intelligence by FPOs etc .

3. SALIENT FEATURES

3.1 Linkage to Marketing Reforms:

3.1.1 State/UT agency non - storage infrastructure projects of those States/Union Territories that have undertaken reforms in their respective APMC Acts to make provision for (i) direct marketing ; (ii) contract Farming; (iii) setting up of wholesale market for agricultural and allied produce in private and cooperative sector; (iv) e-trading; (v) unified single trading license valid across the State/UT and (vi) single point levy of market fee across the State/UT will be eligible for assistance under the sub-scheme.

However, no above such reforms linkage stipulations exist for State/UT agency projects to avail assistance for storage infrastructure projects

Explanation: Hereinbefore, State/UT agency non-storage infrastructure projects mean projects other than storage infrastructure promoted by State/UT Agricultural Marketing Departments/Directorates, State Agricultural Marketing Boards, Agricultural Produce Market Committees, State Warehousing Corporations, State Civil Supplies Corporations etc.

3.1.2 Projects promoted by private entrepreneurs other than state agencies will however be eligible to avail assistance under the sub-scheme, irrespective of the reforms under taken by the State Governments/UTs in their respective APMCs Act.

3.2 Promotion of Farmers Consumer Market and Rural Haats:

3.2.1 Farmer Consumer markets are primarily market place where small and marginal farmers bring agriculture produce to sell directly to consumers and bulk buyers and being located relatively near to farm gate. They provide better and enhanced market access to farmers. They are known by various names Rural Primary Market, village haats, farmer consumer market located mainly in rural areas, outskirts of urban/semi urban/peri-urban areas

apart from some of them being located on peripheries of Cities with better access to farmers. Rural haats play important role in aggregation of farm produce for forward linkages and facilitating farmers/producers in direct sale of their produce to consumers/bulk consumers and reducing intermediaries.

3.2.2 As per budget announcement 2018-19, the existing rural haats develop and upgrade into Gramin Agricultural Markets (GrAMs) by strengthening of physical infrastructure. These GrAMs electronically linked to e-NAM and exempted from regulations of APMCs, will provide farmers facility to make direct sale to consumers and bulk purchasers.

3.2.3 Infrastructure for establishing these markets for selling agricultural commodities from farmer to consumers may be created by all categories of promoters such as Panchayats, APMCs/RMCs, State Agencies, farmers, FPOs/FPCs, individual, Trustee etc. It will be responsibility of the promoter to comply with all the applicable laws.

3.2.4 Infrastructure for development/upgradation to Rural Haats/RPMs as Grameen Agricultural Market may comprise Basic & Supporting infrastructure such as open raised/covered platform, toilet, drinking water facility, drainage, internal road, garbage pit, office, warehouse for storage (small), space for packaging, fencing which are essential for rural haats. The Marketing Infrastructure components such as Drying facility (solar/normal), weighing scale (electronic/normal), assaying equipments, Computer IT equipments with internet connection, Godown, cold room, deep freezer/ Zero energy freezer, pack house, ripening chamber, information boards (electronic/non-electronic), de-sheller, Grain cleaner, specific gravity separator, Mini Dal mill, Mini Oil expeller, Mini rice huller etc are also permissible components allowed under rural haat for better realization of price by the farmers through increased value addition. However, subsidy for Basic & supporting infrastructure in the project will be restricted to 25% of total permissible subsidy of the project. The cost norms for pack house, cold room, ripening chamber, low cost onion storage and zero energy cold chamber is given in **Annexure-V**

3.2.5 These haats are managed by Panchayats/APMCs/Co-operatives/Individuals etc. The State Govt. or agencies nominated by State Govt. may avail the assistance from AMI scheme for development of Marketing Infrastructure for village haats owned/managed by panchayats without duplication of the grant availed for basic and supporting infrastructure from MGNREGA scheme. These hats will provide the better access and thus help in reduce wastages, improving income and rural economy.

3.2.6 The assistance for the infrastructure of the projects for development/upgradation of Rural Haats/RPMs as Grameen Agricultural Market, promoted by the eligible beneficiaries under the scheme in Aspirational Districts identified by the NITI Aayog, shall be given priority.

3.2.7 Rural Haats / RPMs will also be provided with financial assistance for development / upgradation as Grameen Agricultural Market (GrAMs). In case the rural Haats are developed / Upgraded by State agencies including Panchayats then the GrAMs shall be sub-set of the Rural Haats.

3.3 Promotion of Common Facilitation Centre by Farmer Producer Organizations (FPOs) / Farmer Producer Companies (FPCs)

3.3.1 More than 86% of our farmers are small and marginal and thus there is felt need for collectivization/clusterization to facilitate economy of scale for post harvest, value addition and marketing. It provides farmers with the bargaining strength vis-a-vis the market linkages and value chain companies and help them in realization of remunerative prices.

3.3.2 The Farmer Producer Organisations (FPOs) are promoted by various agencies like SFAC, NABARD, and State Governments. The FPOs registered under respective companies Act/cooperatives societies Act/ societies registration Act (with minimum 50 number of farmer members) are playing important role in value addition and marketing of their produce. However to scale up for added strength, they require access to common post harvest and marketing infrastructure facilities at village level near to their farm gate for value addition etc. There is felt need for providing the marketing infrastructure facilities to FPOs/FPCs for common benefit of farmer members. The **Common Facilitation Centre** for FPOs registered under respective companies Act/cooperatives societies Act/ societies registration Act (with minimum 50 number of farmer members) will facilitate member farmers in primary value addition which will help them in enhancing the bargaining power especially for small and marginal farmers, easy market access and income enhancement through better realisation of the prices. The assistance for the projects promoted by FPOs/FPCs in Aspirational Districts identified by the NITI Aayog shall be given priority.

3.3.3 Infrastructure for setting up of Common Facilitation Centre by FPOs/FPCs may comprise common facilities viz. drying facility (solar/normal), electronic weighing scale, assaying equipments, Computer IT equipments, Godown, cold room, deep freezer/ Zero energy freezer, pack house, ripening chamber, information boards (electronic/non-electronic), de-sheller, Grain cleaner, specific gravity separator, Mini Dal mill, Mini Oil expeller, Mini rice huller etc. The ancillary / supporting infrastructure viz. parking sheds, internal roads, garbage disposal arrangements, lighting arrangement, drinking water facility, toilets etc. are also permissible components. However, subsidy for ancillary / supporting infrastructure in the project will be restricted to maximum 25% of total permissible subsidy of the project in as explained **Annexure III**. The cost norms for pack house, cold room, ripening chamber, low cost onion storage and zero energy cold chamber is given in **Annexure-V**.

4. ELIGIBLE MARKETING INFRASTRUCTURE:

4.1 As one of the objectives of the sub-scheme is to ensure remunerative prices to the farmers for their produce, activities which are in the nature of either storage or other marketing infrastructure up to primary processing will be covered. Primary processing for the purpose of this sub scheme relates to value addition to a raw agricultural produce which, after processing, does not result in change of product form. Primary processing for which subsidy under AMI is available are those such as cleaning, cutting, de-podding, de-cortication, de-husking, de-sheller, Grain cleaner, specific gravity separator, mini rice huller, drying equipments (solar/normal), bleaching, grading, sorting, packing/bag stitching, labelling,

waxing, ripening, chilling, pasteurization, homogenization, freezing, refrigeration and other value addition activities etc. **Further, Mini Oil expeller for extraction of edible vegetable oil (as per FSSAI but without refining) from indigenous oilseeds (viz. Mustard seed, Sesame seed, Ground nut, Linseed, Mahua, Safflower, Nigerseed Oil, Coconut, Almond and Olive only) and Mini Dal mill for primary processing of pulses, which includes cleaning, grading, sorting, splitting, packaging and labelling for promoting direct marketing, are also eligible. The subsidy for such projects is restricted to the construction of sheds and oil expellers operated up to the power of 7.5 Horse Power (HP).**

The indicative list of eligible and ineligible processing activities are at Annexure II

4.2 Common facilities in the market yards such as platforms for auctioning of the produce, loading, unloading, assembling, drying, cleaning, grading, weighing, mechanical handling and assaying equipments, etc.

The ancillary / supporting infrastructure like parking sheds, internal roads, garbage disposal arrangements, boundary walls, drinking water etc. are also permissible components. However, subsidy for ancillary / supporting infrastructure in the project will be restricted to 25% of total permissible subsidy of the project in as explained **Annexure III**. Stand-alone ancillary / supporting infrastructure project will not be assisted.

4.3 Functional infrastructure for collection / assembling, drying, cleaning, grading, standardization, SPS (Sanitary &Phyto-sanitary) measures and quality certification, labelling, packaging, ripening chambers, waxing, value addition facilities (without changing the product form) etc.

For functional infrastructure projects (other than storage projects) where plant and machinery is to be installed in civil structure, the cost of plant & machinery should be more than 25% of the Total Financial Outlay (TFO) of the project. If it is less than 25%, subsidy will be restricted accordingly as explained in **Annexure IV**. In such cases where the infrastructure is of the nature of storage, the cost of the civil structure will be calculated as per the capacity and cost norms of the storage infrastructure.

4.4 Infrastructure for direct marketing of agricultural commodities from producers to consumers/processing units/ bulk buyers, etc. and infrastructure for farmer-consumers markets as explained under Para 4.5.

4.5 Infrastructure for development/upgradation of Rural Haats/RPMs as Grameen Agricultural Market may comprise common facilities viz. platforms, sheds, drying facility (solar/normal), electronic weighing scale, assaying equipments, Computer IT equipments with internet connection, Godown, cold room, deep freezer/ Zero energy freezer, pack house, ripening chamber, information boards (electronic/non-electronic), de-sheller, Grain cleaner, specific gravity separator, Mini Dal mill, Mini Oil expeller, Mini rice huller etc. The ancillary / supporting infrastructure viz. parking sheds, internal roads, garbage disposal arrangements, lighting arrangement, drinking water facility, toilets etc. are also permissible components.

However, subsidy for ancillary / supporting infrastructure in the project will be restricted to 25% of total permissible subsidy of the project in as explained **Annexure III**. The cost norms for pack house, cold room, ripening chamber, low cost onion storage and zero energy cold chamber is given in **Annexure-V**.

4.6 Mobile infrastructure for post-harvest operations viz. grading, packaging, quality testing etc. including reefer vans, or any other refrigerated vans will be permissible for assistance. However, transport vehicles such as trucks, van, etc. will not be permissible for assistance.

4.7 Storage infrastructure like godowns including stand-alone silos for storage of food grains with necessary ancillary facilities like loading, unloading, bagging facility etc., excluding railway siding are eligible for subsidy. Assistance for storage infrastructure will be available on capital cost of the project including cost of allied facilities like boundary wall, internal road, internal drainage system, weighing, grading, packing, quality testing & certification, fire fighting equipment etc. which are functionally required to operate the project.

Capacity of 50-5000 MT for all categories of promoters across the country and Capacity of 50-10000 MT for State agencies, in all the States/UTs are eligible for claiming subsidy under the sub-scheme.

In case of State Agency storage projects, silos up to 15000 MT can be constructed. However, the cost norms, rate of subsidy percentage and subsidy ceiling amount will remain the same for state agencies for storage projects and the other conditions will remain the same.

There is no provision of assistance for renovation of storage infrastructure projects under the Scheme.

4.8 Infrastructure (equipment, hardware, gadgets, including application software etc) including infrastructures as mentioned under para 4.5 for Common facilitation centres, e-trading, Market information by the Farmers Producers Organizations (FPOs)/FPCs.

4.9 Stand-alone standardised cold storage units as per standards promoted by NCCD up to 1000 MTs is allowed as per the MIDH cost norms for all the eligible beneficiaries subject to eligibility of the subsidy given under para 9.2 for non-storage infrastructure.

4.10 Integrated Value Chain (IVC) Projects (confined up to stage of primary processing only)

Integrated value chain in agriculture marketing denotes a set of inter-linked chain of activities that bring specific agricultural commodity / commodities from harvesting till retailing and for the purpose of this sub scheme may include those activities where value is added to the produce without change in the form of the produce. A value chain can be a vertical linking or a network among various independent business organizations and can involve assembling, cleaning, grading, primary processing, packaging, transportation (only Refrigerated van), weighing, storage, distribution, etc. Modern value chains are characterized by vertical coordination, consolidation of the supply base, agro-industrial processing and use

of standards throughout the chain. **Financially Standalone projects /activities which are in the nature of either storage and/or other marketing infrastructure up to primary processing only will be covered.**

4.11 The above eligible marketing infrastructure projects are however subject to the restrictions provided in the indicative negative list as at **Annexure VI**. DAC&FW may modify or amend the negative list from time to time.

5. ELIGIBLE BENEFICIARIES:

5.1 For creation of storage infrastructure (Capacity 50 - 5000 MTs) and Non- storage infrastructure:

Individuals, Group of farmers / growers, FPOs/FPCs registered under respective companies Act/cooperatives societies Act/ societies registration Act (with minimum 50 number of farmer members); Partnership/ Proprietary firms, Companies, Corporations; Non-Government Organizations (NGOs), Self Help Groups (SHGs); Cooperatives, Cooperative Marketing Federations; Autonomous Bodies of the Government, Local Bodies, Panchayats; State agencies including State Government Departments and autonomous organization / State owned corporations such as Agricultural Produce Market Committees & Marketing Boards, State Warehousing Corporations, State Civil Supplies Corporations etc.

5.2 For creation of storage infrastructure (Capacity 50 – 10,000 MTs):

State agencies including State Government Departments and autonomous organization / State owned corporations such as Agricultural Produce Market Committees & Marketing Boards, State Warehousing Corporations, State Civil Supplies Corporations etc.

5.3 For development/upgradation of farmer-consumer market and Rural Haats/RPMs:

State Govt. or State Govt. agencies nominated by State Govt. for village haat owned/managed by Panchayats, APMCs/RMCs, FPOs/FPCs registered under respective companies Act/cooperatives societies Act/ societies registration Act (with minimum 50 number of farmer members), State Agencies, farmers, Individual, Trustee etc.

6. INSTITUTIONAL LENDING:

Subsidy under the sub-scheme is linked to institutional credit and will be available to only such projects financed by:

6.1 Commercial, Cooperative, Regional Rural Banks, Agricultural Development Finance Companies (ADFCs), State Cooperative Banks (SCBs), State Cooperative Agricultural and Rural Development Banks (SCARDBs), Scheduled Urban Cooperative Banks, Scheduled Primary Cooperative Banks (PCBs), North Eastern Development Financial Corporation (NEDFi), other institutions eligible for refinance by National Bank for Agriculture and Rural

Development (NABARD) or any other financial institution such as State Financial Corporations (SFCs) approved by DAC&FW.

6.2 NABARD co-financed and directly financed marketing infrastructure projects including storage infrastructure projects would be eligible for subsidy where the interest rates are commercial / market related.

6.3 State Government / State Government agency storage infrastructure projects financed by NABARD under Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) / Warehousing Infrastructure Fund (WIF) / NABARD's own funds.

6.4 Projects promoted by cooperatives and financed by National Cooperative Development Corporation (NCDC) or cooperative banks recognized by NCDC in accordance with NCDC's eligibility guidelines.

6.5 State agencies have a choice of investing their own funds rather than going for institutional funding.

7. CHANNELISING AGENCIES FOR RELEASE OF SUBSIDY:

7.1 Subsidy will be released through NABARD for the projects financed by Commercial, Cooperative, Regional Rural Banks, Agricultural Development Finance Companies (ADFCs), State Cooperative Banks (SCBs), State Cooperative Agricultural and Rural Development Banks (SCARDBs), Scheduled Urban Cooperative Banks, Scheduled Primary Cooperative Banks (PCBs), North Eastern Development Financial Corporation (NEDFi), other institutions eligible for refinance by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) or any other financial institution such as State Financial Corporations (SFCs) approved by DAC&FW.

7.2 Subsidy will be released through NCDC for projects financed by NCDC or by cooperative banks recognized by NCDC in accordance with NCDC's eligibility guidelines.

7.3 Subsidy will be released directly by DAC&FW in case of projects promoted by State agencies which propose to invest their own funds without availing any loan.

7.4 In addition to NABARD and NCDC, DAC&FW may authorize Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC) or any other Govt. agency for release of subsidy for credit linked projects of private sector / State agencies including FPOs.

8. PROMOTER'S CONTRIBUTION & TERM LOAN:

8.1 Minimum promoter's contribution should be 20% of the project cost. This should also be ensured at the time of actual expenditure on completion of the project. If it is less than 20%, the actual TFO of the project shall be restricted to 5 times of the promoter's contribution on completion of the project for the calculation of subsidy. Minimum Term loan (including subsidy) to be sanctioned by the Financial Institution (FI) should be 50% of the project cost. The promoter's contribution may vary from 20-50% of TFO and the term loan may vary from 50-80% of the TFO.

8.2 However, Promoter's contribution for storage infrastructure projects of State Government and State Government agencies financed under Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)/ Warehouse Infrastructure Fund (WIF) of NABARD may be relaxed as per their respective fund guidelines.

8.3 Promoter's Contribution in case of own funded State agency projects should be 75% / 66.67% of the project cost as the case may be.

9. SUBSIDY PATTERN:

The sub scheme envisages back-ended capital subsidy for investment in eligible storage, marketing infrastructure projects is as under:

9.1 FOR STORAGE INFRASTRUCTURE PROJECTS:

9.1.1 Capital cost of the project for the purpose of subsidy will be calculated on the project cost as appraised by financial institution or actual cost of eligible components as certified by a Chartered Accountant, whichever is lower subject to the subsidy ceiling per MT as well as overall ceiling given below:

Category	Rate of Subsidy (on capital cost)	Subsidy ceiling		
		50- 1000 MT in Rs./MT	More than 1000 MT and up to 10,000 (in Rs./MT)	Maximum ceiling (Rs. Lakhs)
A) North Eastern States, Sikkim, UTs of Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, hilly* areas	33.33%	1333.20	1333.20	133.20
B) In other Areas				
1. For Registered FPOs, Panchayats, Women, Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST) entrepreneurs or their cooperatives**/ Self-help groups	33.33%	1166.55	1000.00	100.00
2. For all Other categories of beneficiaries	25%	875/-	750/-	75.00

* Hilly area is a place at an altitude of more than 1,000 meters above mean sea level.

** SC/ ST Cooperatives to be certified by the concerned officer of the State Government.

9.1.2 Cost norms for computing subsidy for silos will be same as for other storage infrastructure.

9.2 FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS OTHER THAN STORAGE (NON-STORAGE) INFRASTRUCTURE INCLUDING FARMER-CONSUMERS MARKET AND DEVELOPMENT AND UPGRADATION OF RURAL HAATS/RPMs into GrAMs : Capital cost of the project for the purpose of subsidy will be calculated on the Project cost as appraised by financial institution or actual cost of eligible components as certified by a Chartered Accountant, whichever is lower.

Category	Rate of Subsidy (on capital cost)	Maximum Subsidy Ceiling # (Rs. in lakhs)
A) North Eastern States, Sikkim, States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, UTs of Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, hilly* and tribal areas	33.33%	30.00 Lakhs
B) In Other Areas		
1. For Registered FPOs, Panchayati Raj Institutions, Women farmers/ entrepreneurs, Scheduled Caste(SC)/ Scheduled Tribe (ST) entrepreneurs and their cooperatives**	33.33%	30.00 Lakhs
2. For all Other categories of beneficiaries	25%	25.00 Lakhs

* Hilly area is a place at an altitude of more than 1,000 meters above mean sea level.

** SC/ ST Cooperatives to be certified by the concerned officer of the State Government

For the projects of pulse splitting and oil crushing, the maximum subsidy for 25% category is Rs.12.50 lakh and 33.33% category is Rs.16.66 lakh only.

9.3 SUBSIDY CEILING:

9.3.1 The total subsidy which can be availed of by a promoter for all his/her projects in a District since inception of the scheme (erstwhile GBY) up to the end of 2019-20 will be restricted to a maximum capacity ceiling of 10,000 MT. if a promoter intends to have more than one project of different type including storage project in the same District he/ she will be eligible for a maximum subsidy up to Rs.75 lakh or Rs. 133.20 lakh as the case may be.

9.3.2 For such cases, RO, NABARD may conduct necessary enquiry to ensure the compliance of this provision regarding maximum permissible limit and if necessary, NABARD may also refer such cases for special attention of Joint Inspection Committee.

9.3.3 To determine the eligibility of projects for maximum permissible subsidy, the date of sanction of loan by FI should be between **22.10.2018 to 31.03.2020**.

9.3.4 There will be no maximum ceiling on subsidy in the case of infrastructure projects of State agencies. However, this is not applicable for storage infrastructure projects of State agencies.

9.3.5 **Co-ownership projects:** In case of infrastructure projects including storage infrastructure projects having co-ownership from categories eligible for different rates of subsidy, the subsidy will be available at the lower rate.

10. RELEASE OF FUNDS AND SUBSIDY:

10.1 FOR PROJECTS PROCESSED BY NABARD:

10.1.1 Release of Subsidy by DAC&FW to NABARD: At the commencement of each financial year, based on the Administrative Approval, 50% of the annual budget allocation minus the opening balance at the beginning of the financial year available with NABARD will be released to NABARD by DAC&FW in advance.

The balance allocation will be released upon submission of provisional Utilization Certificate in prescribed format (**Annexure VII**) by NABARD indicating 60% utilization of the total fund available in the current financial year and Audited Utilization Certificate and statement of account relating to grant released in the preceding year.

10.1.2 Advance subsidy: NABARD will release advance subsidy to the FI for keeping the same in a Subsidy Reserve Fund (SRF) account of the concerned borrowers, to be adjusted finally against loan amount. This amount of 50% eligible subsidy would be released by NABARD to the FI on submission of a project profile-cum-claim form (**Annexure-VIII**) complying to sub scheme guidelines.

11.1.3 Final subsidy: Remaining 50% of the eligible subsidy amount will be released to the FI by NABARD after an inspection and recommendation by a Joint Inspection Committee (JIC) comprising of officers from NABARD (or its representative), FI and Directorate of Marketing & Inspection (DMI).

10.1.4 NABARD, HO will forward a compiled project-wise list of the sanctioned and completed projects to the Head Office of DMI on monthly basis.

10.1.5 The release of subsidy by NABARD to FIs will be subject to availability of funds from DAC&FW.

10.2 FOR PROJECTS PROCESSED BY NCDC:

10.2.1 At the start of each financial year, based on the Administrative Approval, 50% of the projected annual requirement minus the opening balance at the beginning of the financial year available with NCDC will be released to NCDC by DAC&FW in advance. The balance of the requirement will be released upon submission of Provisional Utilization Certificate in prescribed format by NCDC indicating 60% utilization of the total fund available in the current financial year and Audited Utilization Certificate and statement of account relating to grant released in the preceding year.

10.2.2 NCDC will release subsidy in two equal instalments of which first instalment will be released on approval of the project and the second instalment will be released after inspection of the project. NCDC will release the final subsidy and send a project-wise copy of the release letter to DMI, HO. NCDC will furnish provisional utilization certificate in prescribed format (**Annexure VII**) to DMI, HO after every release of fund from DAC&FW.

10.2.3 NCDC, HO will forward a compiled project-wise list of the sanctioned and completed projects to the Head Office of DMI on monthly basis.

10.2.4 The release of subsidy by NCDC will be subject to availability of funds from DAC&FW.

10.3 FOR OWN FUNDED STATE AGENCY PROJECTS:

In the case of own funded State agency projects, subsidy will be released directly by DAC&FW in two equal instalments of which first instalment will be released on approval of the project by the Project Sanctioning Committee and the second instalment will be released after inspection of the project. The release of subsidy will be subject to availability of funds with DAC&FW.

11. ADJUSTMENT OF SUBSIDY IN BORROWER'S ACCOUNT

11.1 As the adjustment of subsidy is back ended, the full project cost including the subsidy amount, but excluding the margin money contribution from the promoter, will be disbursed as loan by the FI. The repayment schedule will be drawn on the loan amount in such a way that the total subsidy amount is adjusted after the full loan component with interest is liquidated but not before five years from the date of disbursement of first instalment of loan.

11.2 The subsidy admissible to the promoter under the sub scheme will be kept in the Subsidy Reserve Fund Account (Borrower-wise) in the books of the FI. On receipt of subsidy by the FI, the loan amount to that extent would be treated as reduced for calculation of interest. No interest would be charged on subsidy received by the FI from the date of receipt of subsidy. FI has to ensure that the subsidy is kept in SRF account only and not in fixed deposits, savings account etc.

12. TIME SCHEDULE FOR SUBMISSION OF APPLICATION AND COMPLETION OF PROJECT:

12.1 FOR DISBURSEMENT OF ADVANCE SUBSIDY: FI will within **60** days of disbursement of the first instalment of loan, submit to RO, NABARD, through its controlling / nodal office, a brief project profile-cum-claim form for advance subsidy in the prescribed form given in **Annexure-VIII** along with the documents as per check list at **Annexure-IX**. A copy of the claim form along with all documents should also be submitted to the Regional Office / Sub-Office of DMI. FI will also inform the promoter about submission of the proposal to RO, NABARD & DMI. NABARD will submit a list of all the advance subsidy claims received at their end to the concerned DMI RO/SO on monthly basis. NABARD on regular basis will take up the matter of timely submission of advance subsidy claims with SLBC.

12.2 FOR ALL CREDIT LINKED PROJECTS PROCESSED BY NABARD AND NCDC:

The time schedule for completion and submission of documents for final subsidy will be as follows:

Time limit* for submission of documents after completion of project for final subsidy	Extended time limit with penalty	Penalty for extended time limit	Consequences of non-submission of documents after completion of project in prescribed time
18** Months from the date of disbursement of the first instalment of loan	Extension of time limit by 6 months will be allowed subject to penalty as explained in next column.	<p>Rate of subsidy will be reduced by 0.5 % for delay of each month or part thereof.</p> <p>Delay by 1 day to 30 days would constitute one month and a delay by 31 days to 60 days would constitute two months and so on.</p> <p>(eg.: in case of a project eligible for 25% subsidy, if after completion of project, documents are not submitted within the prescribed time period but are submitted in 4th month of the extended period, the permissible subsidy will be reduced by 2 % i.e. effective subsidy in this case 25% - 2% = 23% subsidy).</p>	<p>The project will not be eligible for subsidy if documents are not submitted after completion within prescribed time period (including extended period of 6 months).</p> <p>Advance subsidy released will have to be refunded forthwith by the FI.</p>

* For the purpose of calculation of time limit, the date of completion of the project will be reckoned as the date of submission of latter of the following two documents (completion certificate signed by approved engineer / registered architect and item-wise actual expenditure by chartered accountant) by the promoter to the FI.

** For projects promoted by cooperative and processed through NCDC, further grace period of 6 months may be allowed by NCDC.

12.3 FOR OWN FUNDED STATE AGENCY PROJECTS:

Time limit* for submission of documents after completion of project for final subsidy	Extended time limit with penalty	Penalty for extended time limit	Consequences of non-submission of documents after completion of project in prescribed time
Time limit of 30 months from the date of approval of the project by the Sanctioning Committee of DAC&FW	Extension of time limit by 6 months will be allowed subject to penalty as explained in next column.	<p>Rate of subsidy will be reduced by 0.5% for delay of each month or part thereof.</p> <p>Delay by 1 day to 30 days would constitute one month and a delay by 31 days to 60 days would constitute two months and so on.</p> <p>(eg.: in case of a project eligible for 25% subsidy, if progress report for final subsidy is not submitted within the prescribed time period but are submitted in 4th month of the extended period, the permissible subsidy will be reduced by 2% i.e. effective subsidy in this case 25% - 2% = 23% subsidy).</p>	<p>The project will not be eligible for subsidy if documents are not submitted after completion within prescribed time period (including extended period of 6 months) to FI / DMI as the case may be.</p> <p>Advance subsidy released will have to be refunded forthwith.</p>

*For the purpose of calculation of time limit, the date of completion of the project will be reckoned as the date of submission of latter of the following two documents (completion certificate signed by approved engineer / registered architect and item-wise actual expenditure by chartered accountant) by the State agency to the FI/DMI, as the case may be.

13. LAND AND LOCATION

13.1 On the basis of economic viability and commercial considerations, promoters will be free to locate the marketing infrastructure projects including storage infrastructure projects at any place of their choice. However, storage infrastructure projects should be outside the limits of Municipal Corporation areas except in cases where these are situated within Food Parks, Market Yards / APMCs, Industrial areas established or approved by State or Central agencies etc.

13.2 Normally, marketing infrastructure projects including storage projects should be established on land owned by the promoter.

Subsidy will also be available for projects constructed on registered leased land allotted by Urban Development Authorities, Industrial Development and Infrastructure Corporations of the State Government/ Union Territories, Food Parks sanctioned by the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) etc. In all other cases, subsidy will also be made available for projects established on registered leased land, provided the tenure of such lease is more than 15 years from the date of sanction of term loan of project.

13.3 Permissible cost of the land in TFO:

(i) In case of owned land, land cost at market value or purchase price as indicated in the registered sale deed whichever is lower, not exceeding 10% of the project cost may form part of promoter's contribution.

(ii) In case of leased land, allotted by Urban Development Authorities, Industrial Development and Infrastructure Corporations of the State Government/ Union Territories, Food Parks sanctioned by the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) etc., irrespective of the tenure of the lease, lease premium paid or onetime cost paid not exceeding 10% of the project cost may form part of promoter's contribution.

(iii) For other leased land, land cost / lease premium / lease rent will not be counted towards project cost for the calculation of subsidy and will not form part of promoter's contribution.

14. CAPACITY OF STORAGE INFRASTRUCTURE PROJECTS:

14.1 The capacity of storage infrastructure projects will be calculated @ 1.8 MT per square meter of floor area for projects having average height of 4.5 meter and above. For storage infrastructure having average height less than 4.5 meters, the capacity will be calculated @ 0.4 MT per cubic meter of storage volume. The height of the storage infrastructure will be measured from the floor level to the bottom of the truss. In case of storage infrastructure with RCC roof, the height to be considered will be height of the ceiling minus one meter.

14.2 Capacity of silos will be calculated @ 0.62 MT per cubic meter volume of silo.

15. IMPORTANT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR STORAGE INFRASTRUCTURE PROJECTS:

15.1 Storage infrastructure projects to be built under the sub scheme should be constructed based on structurally sound engineering design and should also be functionally suitable for storage of agricultural produce.

One of the objectives of promoting investment in storage infrastructure is to facilitate remunerative prices to farmers for their agricultural produce through the mechanism of Negotiable Warehousing Receipt System (NWRS). Therefore, if storage infrastructures conform to specifications prescribed by Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) it would facilitate taking advantage of NWRS subsequent to such warehouse accredited and registered with WDRA. Specifications as detailed below are to be followed.

15.2 STRUCTURAL SPECIFICATIONS:

15.2.1 As prescribed by WDRA for NWRS, warehouses are to be constructed as per Central Warehousing Corporation (CWC) or Food Corporation of India (FCI) standards.

15.2.2 For storage of Onions, specifications prescribed by National Horticulture Research & Development Foundation (NHRDF) should be followed.

15.2.3 For permissible cold storage projects, ripening chamber etc., the technical specifications of MIDH available at www.midh.gov.in should be followed.

15.2.4 For permissible cold storage projects, ripening chamber etc., the technical specifications of MIDH available at www.midh.gov.in should be followed.

15.2.5 For permissible cold storage as a part of Grading and Infrastructure standalone project, ripening chamber etc., the technical specifications of MIDH available at www.midh.gov.in should be followed.

16. OTHER TECHNICAL SPECIFICATION:

Structure should

- a) be properly ventilated, have well fitted rolling shutters/ steel doors, air inlets/ windows and ventilators and should be waterproof (control of moisture from floor, walls and roof etc).
- b) have a minimum plinth height of 2.5 feet. However, for smaller storage infrastructures (up to 500 MT), plinth height should be a minimum of 1.5 feet.
- c) have protection from rodents, a minimum plinth projection of 1.5 feet all around the storage infrastructure should be provided. However, for smaller storage infrastructures (up to 500 MT), a minimum plinth projection of 1.5 feet at the entry points for protection from rodents should be provided.

- d) have protection from birds (air inlets / ventilators with wire mesh).
- e) have a proper approach road, internal roads, proper drainage, arrangements for effective control against fire and theft and also have arrangements for easy loading and unloading.
- f) only removable steps are to be provided.

17. MANAGEMENT PRACTICES FOR STORAGE INFRASTRUCTURES

In addition, WDRA has prescribed certain management practices, such as fire fighting equipments, security arrangement, appointment of technical staff, availability of chemicals for preservation of agricultural produce, lab facilities, weighment facilities and insurance and banking etc. The promoter and their technical staff may be trained on accreditation and registration with WDRA.

17.1 All new technology innovation such as pre-engineering building structures will also be eligible.

17.2 On need basis, for specific commodities and any innovation, DAC&FW may modify these specifications from time to time.

18. PLEDGE FINANCE:

The farmers keeping their produce in the storage infrastructure will be eligible to avail pledge loan on hypothecation of their produce. The terms and condition governing pledge loans viz. margin, rate of interest, period of pledge, amount etc. will be as per the guidelines issued by RBI / NABARD and as per normal banking practices followed by the Financial Institutions.

In order to discourage distress sale by farmers and to encourage them to store their produce in warehouses against warehouse receipts, benefit of applicable interest subvention will be available to banks for extending credit support to small and marginal farmers having Kisan Credit Card against negotiable warehouse receipt for keeping their produce in warehouses.

19. PROCEDURE TO BE FOLLOWED FOR SANCTIONING OF PROJECTS AND RELEASE OF SUBSIDY

19.1 PROJECTS PROCESSED BY NABARD

19.1.1 Promoter will submit the project proposal for term loan including subsidy to the financial institution (FI) on prescribed application form of the concerned FI complete in all respects and along with project report (DPR) and other documents including forward and backward linkages for appraisal and sanction of term loan to the financially viable and self sustained projects.

19.1.2 On sanction of term loan, the FI will, along with the sanction letter hand over a list of instructions for compliance by the promoter. FI may procure a copy of instruction duly signed by the promoter as a token of their acknowledgement. This list of instructions is provided at **Annexure X**

19.1.3 FI, will within **60** days of disbursement of the first instalment of loan, submit to RO, NABARD, through its controlling / nodal office, a brief project profile-cum-claim form for advance subsidy in the prescribed form given in **Annexure – VIII** along with the documents as per check list at **Annexure-IX**. A copy of the claim form along with all documents should also be submitted to the Regional Office / Sub-Office of DMI. FI will also inform NABARD will submit a list of all the advance subsidy claims received at their end to the concerned DMI RO/SO on monthly basis. NABARD on regular basis will take up the matter of timely submission of advance subsidy claims with SLBC.–the promoter about submission of the proposal to NABARD and DMI.

19.2 RELEASE OF ADVANCE SUBSIDY:

On receipt of claim form and documents complete in all respect as mentioned in preceding Para, RO, NABARD, will sanction the advance subsidy, to eligible projects complying to sub-scheme guidelines, within **60** days of receipt of claim. Subject to availability of funds, RO, NABARD will release soon thereafter advance subsidy to the FI for keeping the same in Subsidy Reserve Fund (SRF) account of the promoter. RO, NABARD will forward a copy of sanction and release letter for each project to Regional/ Sub-office of DMI. In case, there are some documents / information missing, RO, NABARD would request the concerned FI to forward the same at the earliest. A copy of this communication is to be endorsed to DMI, RO / SO for follow up action. NABARD, RO will compile month wise, list of the sanctioned projects and advance subsidy released and forward it to DMI RO/ SO. NABARD, HO will compile month wise, list of the sanctioned projects and advance subsidy released and forward it to the Head Office of DMI.

19.3 JOINT INSPECTION AND RELEASE OF FINAL SUBSIDY:

After completion of the project, the promoter will inform the FI of the same and also submit documents as detailed in **Annexure-XI** (including completion certificate signed by approved engineer / registered architect and item-wise actual expenditure by chartered accountant signed by the promoter and countersigned by the Branch Manager of FI) to the FI within the prescribed time limit. Within 60 days of the receipt of relevant documents from the promoter, the FI will submit to RO, NABARD and Regional/ Sub-office of DMI, final subsidy claim in **Annexure-XII** along with necessary documents, complete in all respects and also request for Joint Inspection of the project.

19.3.1 NABARD will initiate action to conduct joint inspection by a team comprising of officials of FI, NABARD (or its representative) and DMI to ensure that the executed project conforms to technical and financial parameters. The joint inspection will be done within 60 days of the receipt of documents / information from the FI. The joint inspection report should

be as per **Annexure-XIII**. Geo-tagged photograph of the project may also be taken by representative of FI.

19.3.2 If the project is in order, immediately after joint inspection, FI will forward the joint inspection report along with requisite documents to NABARD, RO within 60 days of JMI. NABARD, RO will sanction the final subsidy within **60** days and release soon thereafter final subsidy to the FI for keeping the same in Subsidy Reserve Fund Account (Borrower-wise). NABARD, RO will also forward a copy of sanction and release letter for each project to Regional/ Sub-office of DMI. NABARD, HO will compile month wise, list of the sanctioned projects and final subsidy released and forward it to the Head Office of DMI.

19.3.3 In case any deficiencies are pointed out by the joint inspection committee, the promoter must be informed of the same by FI and asked to rectify. The compliance of rectification thereof will be verified by the FI and report to this effect will be furnished by the FI to NABARD & DMI within 60 days of joint inspection. Remaining procedure will be the same as outlined in above Para for release of final subsidy.

19.3.4 Joint Inspection of completed projects will be conducted subject to the project having been scrutinized by NABARD RO and found to be eligible for advance subsidy. However, the actual release of advance subsidy by NABARD is not necessary for conduct of joint inspection.

19.3.5 The time schedule prescribed in Para 13 must be adhered to for completion of project and submission of relevant documents complete in all respect, failing which, the project will not be eligible for subsidy. The advance subsidy in all such cases will have to be refunded forthwith by the FI.

19.3.6 NABARD, HO will furnish utilization certificate in prescribed format to DMI, HO after every release of fund from DAC&FW. Participating FIs should also submit the utilization certificate in **Annexure-XIV** to NABARD, RO within 60 days of receipt of subsidy.

19.3.7 Panchayati Raj Institutes (PRIs) will have an important role in ensuring that the infrastructure created / proposed is used for the purpose for which it is designed. To enable PRIs play this role effectively, District Panchayats will be kept informed by NABARD RO of all the projects approved and subsidy disbursed in their areas. District Panchayats may share this information with concerned Block / Gram Panchayats. In areas where part IX of the constitution does not apply, this information will be shared with equivalent rural local bodies.

19.4 PROJECTS PROCESSED BY NCDC

19.4.1 For agricultural marketing infrastructure projects including storage infrastructure projects of cooperative institutions, processed by NCDC, cooperative societies will formulate proposals in the format prescribed by NCDC and will submit to Registrar of Cooperative

Societies (RCS) / State Government. The proposal may be submitted directly to NCDC, in case the society concerned fulfils the direct funding norms of NCDC.

19.4.2 The RCS/State Government will examine the proposal and recommend to NCDC for consideration.

19.4.3 NCDC will consider the proposals by way of desk/field appraisal according to the quantum of assistance involved.

19.4.4 NCDC will communicate its sanction to the State Government / directly to the society concerned (in case of direct funding).

19.4.5 The pattern of funding, interest rates, mode of release of sanctioned assistance will be as per NCDC's norms and policies as circulated from time to time.

19.4.6 The sanctioned assistance will be released through the State Governments or directly to the societies (in case of direct funding). NCDC will release subsidy in two equal instalments of which first instalment will be released on approval of the project and the second instalment will be released after inspection of the project.

19.4.7 NCDC will conduct inspection of all the sanctioned projects before releasing final instalment of subsidy. Geo-tagged photograph of the project will be attached with the Inspection Report.

19.4.8 The State Governments / society concerned (in case of direct funding) will provide progress reports of projects on periodic basis as required by the NCDC.

19.4.9 NCDC, HO will compile month wise, a list of the sanctioned projects for advance and final subsidy and forward it to the Head Office of DMI. NCDC, HO will furnish utilization certificate in prescribed format to DMI, HO after every release of fund from DAC&FW.

19.5 OWN FUNDED STATE AGENCY PROJECTS FOR CREATION OF STORAGE / NON-STORAGE INFRASTRUCTURE:

19.5.1 State agencies that do not wish to avail loan from FIs, may submit the project proposal to DMI RO/SO directly in **Annexure-XV** complete in all respects along with project report (DPR) including forward and backward linkages. The proposal should reach DMI within 60 days of approval accorded by the authorities concerned. Subordinate State agencies, such as, APMCs, Local Bodies etc. should submit their proposals to DMI through their State level Organizations/ Departments concerned. A copy of the complete set of proposal may also be endorsed to DMI, HO, Faridabad.

19.5.2 DMI, RO/SO after obtaining the approval from DMI, HO, will send the proposal for appraisal to NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd. (NABCONS), a wholly owned subsidiary of NABARD or any other suitable FI empanelled by the Ministry. However, project proposals which have been prepared by NABCONS or any other FI empanelled by the Ministry and have Feasibility Report and Cost-Benefit Analysis in their Detailed Project Report (DPR), need not be referred again for appraisal by these agencies. The project development facility (PDF) under the sub scheme available with Ch. Charan Singh National

Institute of Agricultural Marketing (NIAM), may also be availed for preparing such DPRs. The fees for appraisal of such projects will be borne by the concerned State Agency.

19.5.3 NABCONS or the FI concerned will appraise the project proposal within 90 days of receipt from DMI and forward the proposal with recommendations to the DMI, RO/SO. The DMI, RO/SO will forward the proposal to DMI, HO for placing before the Committee constituted under the Chairmanship of Agricultural Marketing Adviser to the Government of India. The committee will comprise of a representative of concerned State agency, a representative from the Marketing Division of DAC&FW and from IFD of DAC&FW, an expert from FCI/ CWC/ WDRA / MoFPI / NHM etc, a representative of appraisal agency and a representative of concerned Regional/ Sub-Office of DMI as member Secretary. The proposals which do not need appraisal will be considered directly by the Committee on their receipt in DMI.

19.5.4 The Committee will examine and approve the projects found suitable for subsidy within 90 days of receipt of the recommendations of appraisal agency.

19.5.5 Subsidy will be released to the State agency concerned directly by DAC&FW in two equal instalments depending on the progress of the work. The advance subsidy will be released on approval of the project by the Project Sanctioning Committee.

19.5.6 State Government agency on completion of the project will request for joint inspection of the project within the prescribed time period. While making such a request, the agency will also enclose certificates regarding item-wise physical progress from their approved engineer / registered architect and certificate regarding item-wise financial progress from Chartered Accountant along with final subsidy claim in **Annexure-XVI**

19.5.7 Any cost escalation or change in quantity of works etc. over and above the original project proposal sanctioned by Sanctioning Committee will have to be met by the State agency concerned, before seeking release of the final subsidy.

19.5.8 The joint inspection of the project will be conducted by a committee comprising of officers of DMI and representative of the concerned State agency.

19.5.9 The inspection report in **Annexure-XVII** will be submitted by concerned state agency to DMI, RO/SO for the release of final subsidy within 45 days of joint inspection. Photograph of the project will also be attached with the inspection report.

19.5.10 On receipt of final subsidy claim from DMI, RO / SO, DMI, HO will process the claim within 90 days and submit to DAC&FW for release of final subsidy.

19.5.11 The time schedule prescribed in Para 13 must be adhered to for submission of progress report for final subsidy along with relevant documents complete in all respect, failing which, the project will not be eligible for subsidy. The advance subsidy in all such cases will have to be refunded forthwith by the State agency.

19.5.12 State agency concerned will furnish utilization certificate in prescribed format **Annexure-VII** to DMI, HO through DMI, RO / SO after every release of fund from DAC&FW.

19.5.13 The monitoring of progress of these projects will be done by DMI through its Regional / Sub Offices. DMI, RO / SO will also maintain all data / information.

20. OTHER CONDITIONS

20.1 The project should be commenced only after term loan is sanctioned for the project proposal by the FI / NCDC. However, the promoter may invest up to the margin money contribution in the project before the sanction of term loan by FIs. Such investment before the sanction of term loan shall be excluded for the calculation of subsidy. In case of own funded state agency projects, the project should be commenced only after approval of the project proposal by Project Sanctioning Committee of DAC&FW is received. Own funded State Agency projects shall only be considered for sanctioning of advance subsidy after the approval of plan of the project by the local authority.

20.2 If a case arises for refund of subsidy, and the subsidy is not refunded by the FI to NABARD within 90 days of intimation, the FI will attract penal interest @ bank rate + 1%. In no case, will it be charged to the promoter.

20.3 The FI/NCDC/NABARD etc., will adhere to their own norms for appraisal of projects for sanction of term loan.

20.4 It will be the responsibility of the promoter to comply with all the applicable laws, obtain requisite approvals from the concerned authorities to build and operate the projects as well as to insure the project. DAC, DMI, NABARD or NCDC will not be responsible for any such violation by the promoter.

20.5 The promoter may be informed about the deficiencies pointed out by the joint inspection committee at the time of inspection for compliance.

20.6 A prominent signboard at the site of the project stating "Assisted under Integrated Scheme for Agricultural Marketing of Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India" in local language/ Hindi / English will be exhibited.

20.7 Government's interpretations of various terms of these guidelines will be final. Government reserves the right to modify, add and delete any term and condition and restrict / stipulate any provision without assigning any reason thereof.

20.8 Besides Joint Inspection, pre and post-completion inspections of the project may be undertaken to verify physical, financial and operational progress, as and when required, by DAC&FW or any other agency approved by DAC&FW.

20.9 The promoter will not alienate the land and the project during the period of the term loan for any purpose other than the purpose for which the subsidy is extended. An affidavit to this effect should be submitted by the promoter with the application for loan.

20.10 No subsidy / grant shall be availed of for the project proposal submitted under sub scheme of AMI from any other Central Government scheme including Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) / MGNREGA. An Affidavit to the effect that subsidy has not been availed of and will not be availed of from any other Scheme of the Central Government will be submitted along with the application.

20.11 The promoter will be liable to refund the subsidy of the project or its component that is dropped / cancelled or if any change is made in any of the components of the project sanctioned. Affidavit to this effect will be submitted by the promoter at the time of submission of the project proposal.

20.12 The promoter will take prior approval of NABARD / NCDC in case of takeover of loan account together with Subsidy Reserve Fund (SRF) account by another FI (without altering the repayment schedule) is intended.

20.13 Assistance under the sub scheme will be available only on capital cost of the project.

20.14 The promoter will submit a notarized affidavit as per **Annexure - XVIII**

20.15 An Empowered Committee constituted under the chairmanship of Additional Secretary (DAC&FW) and composed of Joint Secretary (Marketing) / Agricultural Marketing Adviser, Director (Marketing), Joint Agricultural Marketing Adviser and Director / Deputy Secretary (Finance), IFD, DAC&FW will resolve difficulties and smaller case to case specific decisions on implementation issues

20.16 DAC&FW may claim up to 0.5% of the scheme funds at its level for incurring administrative expenditure towards more effective Management Information System (MIS), monitoring, impact assessment, hiring consultants, conducting studies, publicity, advertisement, training, evaluations, study tours, extension, preparation of Model projects and any other facilitative mechanism for more effective implementation of the sub scheme.

20.17 NABARD, NCDC will be provided processing charges of 0.5% of the total subsidy released by them towards activities such as processing of projects, inspection, monitoring, hiring consultants, for developing and maintaining MIS, Geo-tagged photographs, training, publicity, study, evaluation etc. These agencies after obtaining the approval of DAC&FW, authorized to debit the processing charge on release of final subsidy from the funds received from DAC&FW and the same will be accounted for in the utilization certificate to be submitted by them.

20.18 On establishment of MIS, the procedure for release of subsidy may be implemented through online mode.

20.19 The FI after sanction of the project should monitor the progress of the project. In case, for any reason there is variation in the project, subsidy would be restricted to the original proposal or to actual whichever is lower.

20.20 DAC&FW through DMI HO/ROs/SOs or any other approved agency may take up random check inspection of 5% of projects for which final subsidy is released, to verify the utilization of the project for which it is intended, on yearly basis. Needful action will be taken based on the inspection report.

20.21 All earlier instructions issued by DAC/DMI in respect of GBY, AMIGS and AMI schemes will stand superseded with the issue of these new Operational Guidelines for the creation of projects under this scheme.

20.22 The new guidelines will be effective for the projects for which term loan is sanctioned by FIs / NABARD/NCDC and own funded State agency projects approved by DAC&FW on or after **22.10. 2018**.

20.23 FIs / NABARD / NCDC / DMI will maintain all data / information separately for each projects sanctioned under this scheme.

21. MONITORING

21.1 The Marketing Division in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare would be the overall in-charge of the policy formulation for the Agricultural Marketing Sector and Directorate of Marketing and Inspection an attached office of the department would be the implementing agency of the scheme.

21.2 Monitoring of each project will be done by FI, NABARD, NCDC and by DMI through its Regional/ Sub offices.

21.3 Review of progress of sub scheme of AMI will be done on quarterly basis by DMI Regional/ Sub offices with concerned ROs of NABARD under the Chairmanship of Chief General Manager (CGM) of NABARD in the concerned State.

21.4 A Regional Coordination Committee (RCC) exists, comprising DMI, NABARD / NCDC and leading bankers in each state including SLBC convenor to review the progress under the scheme, under the Chairmanship of CGM, NABARD. RCC may meet as per need /once in six months.

21.5 NABARD, Regional Office will submit a monthly progress report to their Head Office and to concerned Regional / Sub Offices of DMI. Review of progress of cooperative projects will be done as per need / once in six months by DMI, RO/SO with NCDC.

21.6 Annual meetings will also be held at DAC&FW level with NABARD, NCDC and NIAM Officials under the Chairmanship of Joint Secretary (Marketing) / AMA.

21.7 NABARD, RO / NCDC, RO and DMI, RO / SO will also monitor each project for conducting Joint Inspection and for timely release of subsidy.

21.8 The progress report of the sub scheme will be submitted by NABARD, HO/NCDC, HO/NIAM directly to the Head office of DMI on a monthly basis as per **Annexure-XIX**

21.9 MIS online application processing and monitoring will be developed by the NABARD.

21.10. NABARD after receipt of proposal from FIs, shall sanction the subsidy on first come first serve basis. NABARD, while sanctioning the subsidy, shall ensure that the amount of sanction of subsidy shall not exceed the budget allocation provided under the scheme.

22. GENERAL AWARENESS AND TRAINING PROGRAMME

General awareness, advertisement, publicity and training programmes for farmers, market functionaries, entrepreneurs and other stakeholders in establishment, maintenance and operation of infrastructure projects, registration / accreditation with WDRA and also on agricultural marketing in general including on grading and standardization, will be taken up through Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing (NIAM), Jaipur, National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad, Training of Personnel in Cooperative Institute (TOPIC), Gurgaon, NABARD and other national and state level institution/ Universities etc. General awareness, advertisement, publicity and training programmes will be taken up with a special focus on promoters from SC / ST category & North Eastern Region and in the States / UTs where the sub scheme has not picked up in the past. NIAM would also arrange for consultancy services for setting up of a Project Development Facility to catalyze investment credit in Agri-infrastructure projects.

22.1. FINANCIAL OUTLAY FOR THE PERIOD OF 2017-18 TO 2019-20

(Rs. in crore)

2017-18		2018-19		2019-20		Total	
Recurring	Non-recurring	Recurring	Non-recurring	Recurring	Non-recurring	Recurring	Non-recurring
3.00	1082.00	3.00	455.00	3.00	504.00	9.00	2041.00

List of Regional /Sub-offices of Directorate of Marketing & Inspection with address

<u>Andaman & Nicobar Island</u> Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, General pool Offices Building, 4 th Floor, A Wing, DF Block, Sector-1, Salt Lake, Kolkata -700064 Ph.033- 23347553, 23340845, dmiwb03@nic.in	<u>Dadra & Nagar Haveli</u> Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection New CGO Building, 3 rd Floor, New Marine Lines, Mumbai-400020 Ph.022-22036801,22032699 dmiromah@nic.in
<u>Andhra Pradesh</u> Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection 2 nd Floor, Kendriya Sadan, Sultan Bazaar, Hyderabad -500095 Ph.040- 24657446, 24731637 dmiroap@nic.in	<u>Daman & Diu</u> Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection New CGO Building, 3 rd Floor, New Marine Lines, Mumbai-4000820 Ph.022-22036801,22032699 dmiromah@nic.in
<u>Arunachal Pradesh</u> Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection RUKMINIGAON, Navratna Path, H.No.09, First Floor, P.O.Khanpara Guwahati-781022. Ph. 0361- 2229272, 2229273 dmias01@nic.in	<u>Delhi</u> Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, W-6, Phase II, Okhla Industrial Estate, New Delhi 6 110020 Ph.011-26387285 dmidl06@nic.in
<u>Assam</u> Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection RUKMINIGAON, Navratna Path, H.No.09, First Floor, P.O.Khanpara Guwahati-781022. Ph. 0361- 2229272, 2229273 dmias01@nic.in	<u>Gujarat</u> Senior Marketing Officer, Directorate of Marketing & Inspection 1, Inderprastha Society 1 st Floor, Opp. Shankar Nagar, Near Gandhi Bridge Shahpur, Ahmedabad-380004 Ph. 079-25600965 dmigj03@nic.in
<u>Bihar</u> Senior Marketing Officer, Directorate of Marketing & Inspection Government of India, Pant Bhawan (Ground & First Floor), Baily Road, Patna-800001 Ph. 0612-2526691 dmipatnasm@gmail.com	<u>Goa</u> Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection New CGO Building, 3 rd Floor, New Marine Lines, Mumbai-400020 Ph.022-22036801,22032699 dmiromah@nic.in

<p><u>Chandigarh</u></p> <p>Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, 6th Floor, KendriyaSadan, Sector 9 -A, Chandigarh-160 047 Ph.0172 6 2743201 dmich01@nic.in</p>	<p><u>Haryana</u></p> <p>Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection 6th floor Kendriya Sadan, Sector 9A, Chandigarh-160047 Ph.0172-2743201 dmich01@nic.in</p>
<p><u>Chhattisgarh</u></p> <p>Marketing Officer Directorate of Marketing & Inspection, 33, Anand Nagar, Raipur 6 492001 Ph. 0771-2446030 dmiraipur.cg@nic.in</p>	<p><u>Himachal Pradesh</u></p> <p>Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection 6th floor Kendriya Sadan, Sector 9A, Chandigarh-160047 Ph.0172-2743201 dmich01@nic.in</p>
<p><u>Jammu & Kashmir</u></p> <p>Marketing Officer, Directorate of Marketing & Inspection, 61,A, II Extension, Gandhi Nagar, Jammu Tawi-180004 Ph. 0191-2450478 dmijk01@nic.in</p>	<p><u>Jharkhand</u></p> <p>Senior Marketing Development Officer, Directorate of Marketing & Inspection, Main Terminal Market Yard, Pardra, Ranchi 6 834005 Ph.: 0651- 2512597 dmi_ranchi@yahoo.in</p>
<p><u>Kerala</u></p> <p>Senior Marketing Officer, Directorate of Marketing & Inspection 2nd Floor, Ramakrishna Building, East Thampanoor Thiruvananthapuram-695001 Ph. 0471-2471134 dmikl02@nic.in</p>	<p><u>Karnataka</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection M.G.Complex APMC, Yashwantpur, Bangalore-560022 Ph. 080-23473004 dmilk04@nic.in</p>
<p><u>Lakshadweep</u></p> <p>Senior Marketing Officer, Directorate of Marketing & Inspection 2nd Floor, Ramakrishna Building, East Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 Ph. 0471-2471134 dmikl02@nic.in</p>	<p><u>Maharashtra</u></p> <p>Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection New CGO Building, 3rd Floor, New Marine Lines, Mumbai-400020 Ph.022-22036801,22032699 dmiromah@nic.in</p>
<p><u>Madhya Pradesh</u></p> <p>Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection House No.245, 2nd Floor, M.P.Nagar, Zone -II Bhopal-462 011 Ph.0755-2551847 dirmkti@mp.nic.in</p>	<p><u>Manipur</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection RUKMINIGAON, Navratna Path, H.No.09, First Floor, P.O.Khanpara Guwahati-781022 Ph. 0361-2229272, 2229273 dmias01@nic.in</p>

<p><u>Meghalaya</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection RUKMINIGAON, Navratna Path, H.No.09, First Floor, P.O.Khanpara Guwahati-781022 Ph. 0361-2229272, 2229273 dmias01@nic.in</p>	<p><u>Mizoram</u></p> <p>Asst.Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection RUKMINIGAON, Navratna Path, H.No.09, First Floor, P.O.Khanpara Guwahati-781022 Ph. 0361-2229272, 2229273 dmias01@nic.in</p>
<p><u>Nagaland</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection RUKMINIGAON, Navratna Path, H.No.09, First Floor, P.O.Khanpara Guwahati-781022 Ph. 0361-2229272, 2229273 dmias01@nic.in</p>	<p><u>Orissa</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, General pool Offices Building, 4th Floor, A Wing, DF Block, Sector-1,Salt Lake, Kolkata-700064 Ph.033-23340845,23347553 dmiwb03@nic.in</p>
<p><u>Pondicherry</u></p> <p>Asst.Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection Shastri Bhawan.4 th Floor, 6th Block,26HaddowsRoas, Chennai-600006 Ph.044-28271738, 28278065 dmirotn@nic.in</p>	<p><u>Punjab</u></p> <p>Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection 6thfloo,rKendriyaSadan, Sector 9&A&Chandigarh-160047 Ph.0172-2743201 dmich01@nic.in</p>
<p><u>Rajasthan</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection 4th Floor, KendriyaSadan, Sec.10 Vidyadhar Nagar Jaipur ó 302023 Ph. 0141-2231527 agmarkjpr-rj@nic.in</p>	<p><u>Sikkim</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, General pool Offices Building, 4th Floor, A Wing, DF Block, Sector-1,Salt Lake, Kolkata-700064 Ph.033-3340845,3347553 dmiwb03@nic.in</p>
<p><u>Tamilnadu</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection Shastri Bhawan.4 th Floor, 6th Block,26HaddowsRoas, Chennai-600006 Ph.044-28271738,28278065 dmirotn@nic.in</p>	<p><u>Tripura</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection RUKMINIGAON, Navratna Path, H.No.09, First Floor, P.O.Khanpara, Guwahati-781022 Ph. 0361-2229272, 2229273 dmias01@nic.in</p>

<p><u>Uttar Pradesh</u></p> <p>Deputy Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection 5th Floor, KendriyaBhawan, Hall 2, Sector H, Aligunj, Lucknow-226024 Ph. 0522-2326658 agmark.up@nic.in</p>	<p><u>Uttrakhand</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, W-6, Phase II, Okhla Industrial Estate, New Delhi 6 110020 Ph.011-26387285 dmidl06@nic.in</p>
<p><u>West Bengal</u></p> <p>Asst. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, General pool Offices Building, 4th Floor, A Wing, DF Block, Sector-1,Salt Lake, Kolkata-700064 Ph.033-23340845,23347553 dmiwb03@nic.in</p>	

For further information, please contact:

Deputy Agricultural Marketing Adviser,
Directorate of Marketing & Inspection,
New CGO Building, NH-IV, Faridabad-121 001
Tele: 0129 -2434348
Fax: 0129- 2416568
E-Mail: **rgs-agri@nic.in**

Director General,
National Institute of Agricultural Marketing,
Kota Road, Bambala, Near Sanganer,
Jaipur-303 906
Tele: 0141-2770589, 0141-2770614
Fax: 0141-2770589, 0141- 2770051
E-Mail: **dgniam@hotmail.com**

Chief General Manager, Department of Refinance,
National Bank for Agriculture &
Rural Development,
Plot No. C-24, G Block,
BandraKurla Complex, Bandra East,
Mumbai- 400 051.
Tele: 022- 26539350
Fax: 022-26530090
E-Mail: **dor@nabard.org**

Chief Director (Storage),
National Cooperative Development
Corporation,4, Siri Institutional Area,
HauzKhas,
New Delhi- 110 049.
Tele: 011- 26961170
Fax: 011- 26962370
E-Mail: **mail@ncdc.in**

The indicative list of eligible and ineligible processing activities

	Eligible Activities	Ineligible Activities	
	Primary processing	Secondary processing	Tertiary processing
Fruits & Vegetables	Cleaning, Sorting, Grading, Cutting etc.	Slices, pulps, Soup, flakes, powder, paste, preserved & Flavoured	Ketchups, jam juices, pickles, preserves, candies, chips, etc.
Grains & Seeds	Cleaning, Sorting, Grading, and Splitting of pulses.	Flour, Broken, Rice, Puff, Malt & Milling / Flour milling / Dal milling	Biscuits, noodles, flakes, cakes, Namkeen
Oilseeds and coconut	Cleaning, Sorting, Grading and direct Crushing of indigenous oilseeds and coconut to obtain raw vegetable edible oil (without refining) as specified in FSSAI Act and Regulations thereof.	Oil Cakes	Refined edible oils.
Beverages	Sorting, bleaching & Grading	Leaf, Dust & Powder	Tea bags, flavoured, coffee, soft drinks, alcoholic beverages.
Milk	Grading, Refrigerating	Cottage cheese, Cream, Simmered & Dried Milk,	Processed milk spreadable fats (butter and cheese), Ghee, Yoghurt.
Meat & Poultry	Sorting & Refrigerating	Cut, Fried, Frozen & Chilled	Ready to eat meals.
Marine products	Chilling & Freezing	Cut, Fried, Frozen, Chilled	Ready to eat meals.

The above table is indicative and does not illustrate all processes.

Examples for calculation of eligible subsidy for common facilities and ancillary/ supporting infrastructure in market yards project, eligible @ 25% subsidy

1. Scenario One: ancillary/supporting infrastructure equal to 25% of TFO

(Rs. In lakhs)

Components of Project	Cost	Eligible % of TFO	Eligible cost	Eligible subsidy
Common facilities in market yard	60.00	75%	60.00	15.00
Ancillary/ supporting infrastructure	40.00	25%	20.00	5.00
Total	100.00	100%	80.00	20.00*

* Subsidy will not be Rs. 25.00 lakhs @ 25% of Rs.100.00 lakhs.

2. Scenario two: ancillary/supporting infrastructure more than 25% of TFO

(Rs. In lakhs)

Components of Project	Cost	Eligible % of TFO	Eligible cost	Eligible subsidy
Common facilities in market yard	40.00	75%	40.00	10.00
Ancillary/ supporting infrastructure	60.00	25%	13.33	3.33
Total	100.00	100%	53.33	13.33*

* Subsidy will not be Rs.25.00 lakhs @ 25% of Rs.100.00 lakhs.

3. Scenario three: ancillary/supporting infrastructure more than 25% of TFO

(Rs. In lakhs)

Components of Project	Cost	Eligible % of TFO	Eligible cost	Eligible subsidy
Common facilities in market yard	90.00	75%	90.00	22.5
Ancillary/ supporting infrastructure	60.00	25%	10.00	2.5
Total	150.00	100%	1600.00	25.00*

* Subsidy will not be Rs.37.50 lakhs @ 25% of Rs.150.00 lakhs.

4. Scenario four: ancillary/supporting infrastructure less than 25% of TFO

(Rs. In lakhs)

Components of Project	Cost	Eligible % of TFO	Eligible cost	Eligible subsidy
Common facilities in market yard	120.00	75%	100.00	25.00
Ancillary/ supporting infrastructure	40.00	25%	0.00	0.00
Total	160.00	100%	1600.00	25.00*

* Subsidy will not be Rs.40.00 lakhs @ 25% of Rs.160.00 lakhs.

Examples for calculation of eligible subsidy for functional infrastructure project involving installation of Plant & Machinery is equal or less than 25% of TFO, and eligible @ 25% subsidy

1. Scenario One: Plant & Machinery equal to 25% of TFO (Rs. In lakhs)

Components of Project	Cost	Eligible % of TFO	Eligible cost	Eligible subsidy
Plant & Machinery	25.00	25%	25.00	6.25
Civil structure	75.00	75%	75.00 **	18.75
Total	100.00	100%	100.00	25.00*

* Subsidy will be Rs.25.00 lakhs @ 25% as Plant & Machinery equal to 25% of TFO.

2. Scenario Two: Plant & Machinery less than 25% of TFO (Rs. In lakhs)

Components of Project	Cost	Eligible % of TFO	Eligible cost	Eligible subsidy
Plant & Machinery	20.00	25%	20.00	5.00
Civil structure	100.00	75%	60.00**	15.00
Total	120.00	100%	80.00	20.00*

* Subsidy will not be Rs.30.00 lakhs @ 25% of Rs.120.00 lakhs.

3. Scenario Three: Plant & Machinery less than 25% of TFO (Rs. In lakhs)

Components of Project	Cost	Eligible % of TFO	Eligible cost	Eligible subsidy
Plant & Machinery	25.00	25%	25.00	06.25
Civil structure	100.00	75%	75.00**	18.75
Total	125.00	100%	100.00	25.00*

* Subsidy will not be Rs.31.25 lakhs @ 25% of Rs.125.00 lakhs.

4. Scenario Four: Plant & Machinery less than 25% of TFO (Rs. In lakhs)

Components of Project	Cost	Eligible % of TFO	Eligible cost	Eligible subsidy
Plant & Machinery	15.00	25%	15.00	3.75
Civil structure	115.00	75%	45.00**	11.25
Total	130.00	100%	60.00	15.00*

* Subsidy will not be Rs. 32.5 lakhs @ 25% of Rs.130.00 lakhs.

**** If infrastructure is of the nature of storage, the cost of the civil structure will be as calculated above or as per the capacity and cost norms of the storage infrastructure, whichever is lower.**

COST NORMS

S. No.	Item	Cost Norms
1.	Pack house	Rs. 4.00 lakh / unit with size of 9Mx6M
2.	Cold room (staging)	Rs. 15.00 lakh / unit of 30 MT capacity
3.	Ripening chamber	Rs. 1.00 lakh / MT
4.	Low cost onion storage structure (25 MT)	Rs. 1.75 lakh / per unit
5.	Zero energy cool chamber (100 kg)	Rs. 4000/- per unit
6.	Coconut / Cashew nut / Walnut De-shelling Machine	Rs. 1.00 lakh per unit

Indicative Negative List of Projects which will not be eligible for subsidy under the sub scheme of AMI

1. Combined Harvesters
2. Standalone cold storages
3. Retail shops
4. Silos as part of integrated project
5. Projects related to processing of fruits and vegetables- Soup, flakes, powder, paste, preserved & Flavoured drinks, Ketchups, jam juices, pickles, preserves, candies, chips, etc.
6. Projects related to processing of grain and pulses- Flour, Broken, Rice, Biscuits, noodles, flakes, cakes, Namkeen.
7. Leaf, Dust & Powder, Tea bags, flavoured tea, coffee, soft drinks, alcoholic beverages.
8. Cottage cheese, Cream, Simmered & Dried Milk, flavoured milk spreadable fats (butter and cheese), Ghee, Yoghurt.

GFR 12 A

[(See Rule 238 (1)]

**FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE
FOR AUTONOMOUS BODIES OF THE GRANTEE ORGANIZATION**

UTILIZATION CERTIFICATE FOR THE YEAR..... in respect
of recurring/non-recurring
GRANTS-IN-AID/SALARIES/CREATION OF CAPITAL ASSETS

1. Name of the Scheme

2. Whether recurring or non-recurring grants

3. Grants position at the beginning of the financial year

- (i) Cash in Hand/Bank
- (ii) Unadjusted advances
- (iii) Total

4. Details of grants received, expenditure incurred and closing balances: (Actuals)

Unspent Balances of Grants received years (figure as at SI. No. 3 (iii)]	Interest Earned thereon	Interest deposited back to the Govern- ment	Grant received during the year			Total Available funds (1 + 2- 3+4)	Expenditure incurred	Closing Balances (5-6)
			Sanction No. (i)	Date (ii)	Amount (iii)			
1	2	3	4			5	6	7

Component wise utilization of grants:

Grant-in-aidô General	Grant-in-aidô Salary	Grant-in-aidô creation of capital assets i	Total

Details of grants position at the end of the year

- (i) Cash in Hand/Bank
- (ii) Unadjusted Advances
- (iii) Total

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned:

- I. The main accounts and other subsidiary accounts and registers (including assets registers) are maintained as prescribed in the relevant Act/Rules/Standing instructions (mention the Act/Rules) and have been duly audited by designated auditors. The figures depicted above tally with the audited figures mentioned in financial statements/accounts.
- II. There exist internal controls for safeguarding public funds/assets, watching outcomes and achievements of physical targets against the financial inputs, ensuring quality in asset creation etc. & the periodic evaluation of internal controls is exercised to ensure their effectiveness.
- III. To the best of our knowledge and belief, no transactions have been entered that are in violation of relevant Act/Rules/standing instructions and scheme guidelines.
- IV. The responsibilities among the key functionaries for execution of the scheme have been assigned in clear terms and are not general in nature.
- V. The benefits were extended to the intended beneficiaries and only such areas/districts were covered where the scheme was intended to operate.
- VI. The expenditure on various components of the scheme was in the proportions authorized as per the scheme guidelines and terms and conditions of the grants-in-aid.
- VII. It has been ensured that the physical and financial performance under (name of the scheme has been according to the requirements, as prescribed in the guidelines issued by Govt. of India and the performance/targets achieved statement for the year to which the utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure ô I duly enclosed.
- VIII. The utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure ô II duly enclosed (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications.)
- IX. Details of various schemes executed by the agency through grants-in-aid received from the same Ministry or from other Ministries is enclosed at Annexure ô II (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications).

Date:

Place:

Signature

Signature

Name

Chief Finance Officer

Head of the Organisation

(Head of the Finance)

(Strike out inapplicable terms)

PROJECT PROFILE CUM CLAIM FORM FOR CLAIMING 50% ADVANCE SUBSIDY

(TO BE SUBMITTED BY FINANCIAL INSTITUTION TO NABARD AND DMI)

To,

- (1) Regional Office, NABARD
- (2) Regional/Sub-office of Directorate of Marketing & Inspection (nearest as per addresses enclosed)

AGRICULTURAL MARKETING INFRASTRUCTURE

PART 6 I

(FOR USE BY FINANCIAL INSTITUTION)

1. (i) Name & full Address of project including Tehsil / Taluka / District with telephone number and email ID :
- (ii) Whether located in North East Region/ States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep Island / Hilly Areas/ Tribal Areas :
- 2.(i) Name & full address of promoter with telephone number and email ID :
- (ii) Whether belongs to Registered FPOs/ Women/ SC/ ST/ their cooperatives :
 - a) If yes specify :
- (iii) Whether belongs to State Agencies :
 - a) If yes specify :
- (iv) Whether proprietorship/ partnership :
 - a) If yes, rate of entitlement of subsidy (25% / 33.33%) :
3. Name & full address of financing financial institution with telephone number and email ID :
4. Date of receipt of proposal/application :
5. (a) Date and amount of sanction of term loan by financial institution:
 - (b) Date of disbursement of first instalment of loan and amount disbursed:
6. Type of Infrastructure projects:
(Storage/Other than storage/Farmers Consumer Market/Development/Upgradation of Rural Haats/RPMs into GrAMs):
 - (a) In case project of Farmers Consumer Market/ Development/Upgradation of Rural Haats/RPMs into GrAMs, Please specify, Ownership and management:
 - (b) Major Commodities covered:
 - (c) Distance from the nearest APMC(principle market yard /sub-market) :
 - (d) No. Of Villages / Farmers Covered / benefitted:

7. Rate of entitlement of subsidy for projects (25% / 33.33%):

8. Item-wise financial projections

	As per project report (Rs.)	As approved by FI (Rs.)
i) Storage Infrastructure/ Marketing Infrastructure (Non-Storage)/		
ii) Allied facilities / infrastructure / Plant & Machinery		
a)		
b)		
iii) Cost of civil structure		
iv) Project Cost for processing		
a) Cost relating to primary processing		
b) Cost relating to secondary & other processing		
Total outlay		

9. Means of finance:

	As per project report (Rs.)	As approved by FI (Rs.)
Promoter's contribution		
Term loan		
Total outlay		

10. Subsidy

- a) Total eligible subsidy (Rs.) :
- b) Eligible advance subsidy (Rs.) :
- c) Subsidy from any other agency :
- State Govt. :
- Central Govt. (for other components, if any) :

11. Brief account of the infrastructure to be created under the project

- a) Description of components with cost :
- b) Storage Infrastructure capacity :
- | | | |
|-----------------|-------------------|----------|
| No. of chambers | Size | Capacity |
| | (LxBxH in Meters) | (in MT) |

- c) New unit to be created
- d) Existing unit, if any

12. a) Account No. and IFSC code of FI :

 b) AADHAR no of Promoter :

13. Brief coverage on technical feasibility and financial viability (Enclose along with project report) :

14. Other relevant information including as to whether the storage infrastructure would be for self use/ to be leased out to private or Govt. agencies/ to store farmers produce on rent and commodity to be stored

:

15. Other relevant information:

16. The project has been appraised and found to be technically feasible and financially viable. Appraisal note is enclosed

17. We note that the repayment schedule cannot be altered. We also note that a time limit of 18/ 24 months is stipulated for completion of the project and submission of relevant documents from the date of disbursement of first instalment of loan. Further, if the completion of the project is delayed, a maximum extended period of 6 months with reduction in rate of subsidy @ 0.5 % for delay of each month or part thereof may be allowed for completion of project and submission of relevant documents. We also note that the advance subsidy has to be refunded forthwith if the project is not completed and the relevant documents are not submitted within the above stipulated period and as per the broad parameters of the sub scheme. It is further noted that in case of any delay in refund of subsidy, the financial institution will be liable for payment of penal interest. If subsidy is not refunded within 90 days of intimation, penal interest shall be charged @ bank rate + 1% from the financial institution and not promoter.

18. It is also certified that no subsidy / grant has been or will be availed for the project from any other Central Government Department/ Agency including subsidy under RKVY / MGNREGA.

19. Certified that the project has commenced only after sanction of term loan to the promoter/promoter has invested Rs..... which is% of the TFO, as margin money, before sanction of the term loan.

20. Financial institution will monitor the progress of the execution of the project to ensure that the project is completed as per the technical specifications envisaged in the guidelines of the sub-scheme and project proposal without any variation and within the stipulated time as per the broad parameters of the sub scheme.

21. Certified that the promoter has not availed or will avail maximum subsidy as explained under Para 9 of the operational guidelines.

22. Certified that the financial institution will ensure that the promoter will not alienate the land and the project for a minimum period of term loan for any purpose other than the purpose for which the subsidy is extended.

23. An amount of Rsí í í í í í í (Rupeesí í í í í í í í í í í í) being 50% of the eligible amount of subsidy may please be released in respect of the project for crediting to the Subsidy Reserve Fund Account-Borrower wise. Financial institution confirms that that the subsidy will be kept in SRF Account only and not in other accounts like Fixed Deposits, Saving account etc.

(_____)

Seal and signature of the
Authorized Signatory of Financial Institution

Place:

Date:

Encl: as per Annexure VI

Check List of Documents to be submitted along with Advance Subsidy claim

Document No.	Particulars of document	Remarks ✓
A - 1	Forwarding letter of Controlling / nodal Office of the financing branch. The advance subsidy claim application of financing branch should be routed through the Controlling / nodal Office to NABARD clearly certifying that all documents as per this check list are enclosed. The complete address with telephone/fax numbers of the controlling / nodal office as well as the financing branch are required to be furnished. A copy of the letter together with a copy of the claim application should be endorsed to DMI RO / SO	
A - 2	Advance subsidy claim application as per format in Annexure-V	
A - 3	Copy of project report with item-wise details of costs, total outlay, loan and margin submitted by the promoter with a copy of the technical and financial appraisal report from the FI	
A - 4	Copy of the approved plan/ map and civil drawings clearly indicating the dimensions and capacity.	
A - 5	Copy of the loan sanction letter of the FI along with copies of invoices for purchase of machinery/equipment of infrastructure project if any. Copy of Term Loan Account Statement of the borrower indicating all transactions including disbursement of first instalment of loan	
A - 6	Copy of land documents where the project is going to be established.	
A - 7	FI's certificate on category of the Promoter. In case of SC/ST entrepreneur and Cooperative, certification by the Competent Authority should be obtained.	
A - 8	Notarized Affidavit in Original executed by the promoter on a non-judicial stamp paper as per Annexure XV.	
A - 9	Copy of duly registered partnership deed, if it is a partnership firm, Memorandum& Articles of Association and certificate of incorporation, in case of Private Limited Company etc.	

Instructions for the promoter to be annexed by the FI with loan sanction letter

1. Subsidy under the scheme is not guaranteed and is not a matter of right of the promoter. It is subject to availability of funds and compliance to scheme guidelines as may be interpreted and altered by Government of India with/ without notice.
2. The project should be commenced only after term loan is sanctioned for the project proposal by the FI / NCDC. However, the promoter may invest up to the margin money contribution in the project before the sanction of term loan by FIs. Such investment before the sanction of term loan shall be excluded for the calculation of subsidy. In case of own funded state agency projects, the project should be commenced only after approval of the project proposal by Project Sanctioning Committee of DAC&FW is received.
3. Project should be executed as per the technical specifications as specified in guidelines and as per physical & financial parameters submitted in the project proposal. If there is any variation, subsidy would be restricted to the original proposal or actual whichever is lower.
4. Project should be executed as per the conditions envisaged in the guidelines without any variation.
5. The promoter will not alienate the land and the project during the period of the term loan for any purpose other than the purpose for which the subsidy is extended.
6. No subsidy / grant shall be availed for the project proposal submitted under AMI from any other Central Government scheme including Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) / MGNREGA.
7. The promoter will be liable to refund the subsidy of the project or its component that is dropped /scrapped or if any change is made in any of the components of the project sanctioned.
8. The promoter shall take prior approval of NABARD in case of takeover of loan account (with SRFA) by another FI (without altering the repayment schedule) is intended.
9. It will be the responsibility of the owner to comply with the applicable laws, obtain requisite approvals from the concerned authorities to build & operate the projects as well as to insure the project.
10. A prominent signboard at the site stating "Assisted under sub scheme Agricultural Marketing Infrastructure of Integrated Scheme of Agricultural Marketing of Ministry of Agriculture, Government of India" in local language / English will be exhibited.
11. Government's interpretations of various terms of guidelines will be final. Government reserves the right to modify, add and delete any term and condition and restrict / stipulate any provision without assigning any reason therefore.
12. Promoter is hereby being informed that random check inspection of the project may be conducted within 5 years from the date of disbursement of first instalment of loan, to ensure that the project is being used for the intended purpose. In case of non compliance, needful action including recall of subsidy may be taken.
13. Promoter is hereby being informed that a time limit of 18 months is prescribed for completion of the project from the date of disbursement of the first instalment of loan by the financial institution. The project will not be eligible for subsidy if the project is not completed and document submitted within 18 months from the date of disbursement of first instalment of loan and advance subsidy

received will be refunded forthwith. If reasons for delay are justified, a further extended period of 6 months with deduction of rate of subsidy @ 0.5% per month or part thereof is allowed.

14. In case of Own funded State Agency projects, a time limit of 30 months from the date of approval of the project by the Project Sanctioning Committee of DAC&FW is prescribed for completion of the project. The project will not be eligible for subsidy if the project is not completed and document submitted within 30 months from the date of disbursement of first instalment of loan and advance subsidy received will be refunded forthwith. If reasons for delay are justified, a further extended period of 6 months with deduction of rate of subsidy @ 0.5% per month or part thereof is allowed.

15. It will be the responsibility of the promoter to comply with all the applicable laws, obtain requisite approvals from the concerned authorities to build and operate the projects as well as to insure the project. DAC, DMI, NABARD or NCDC will not be responsible for any such violation by the promoter. In case of non compliance of all the requisite approval / permission, the subsidy will have to be refunded.

16. **For Storage infrastructure** : For storage infrastructure projects the following are required and non compliance to it may render the storage infrastructure ineligible to receive subsidy under the scheme:

a) The project built under the sub scheme shall be structurally sound on account of engineering considerations and functionally suitable to store the agricultural produce as per Central Warehousing Corporation (CWC) or Food Corporation of India (FCI) or any other standard specifications laid down in this behalf may be adopted.

b) Shall be properly ventilated, shall have well fitted shutters, air inlets and ventilators and shall be waterproof (control of moisture from floor, walls and roof etc.).

c) Shall have a minimum plinth height of 2.5 feet and minimum plinth projection of 1.5 feet all around the storage infrastructure for protection from rodents. However, for smaller storage infrastructure up to 500 MT plinth height should be a minimum of 1.5 feet and minimum plinth projection of 1.5 feet at the entry points for protection from rodents.

d) Shall have protection from birds (air inlets / ventilators with wire mesh).

e) The openings such as shutters, air inlets etc. shall be designed in such a manner that the storage infrastructure can be sealed for effective fumigation etc.

f) The Storage infrastructure complex shall have an easy approach road, pucca internal roads, proper drainage, arrangements for effective control against fire and theft and also have arrangements for easy loading and unloading of stocks.

g) Only removable steps are to be provided.

Documents to be submitted to NABARD for taking up Joint Inspection

Docum ent No.	Particulars	Remarks ✓
JM -1	Duly filled in final subsidy claim form in Annexure IX	
JM-2	<p>FI's specific request for taking up Joint Inspection of the project interalia certifying that:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The project has been completed in all respects within the stipulated time period. Advance subsidy of Rs. lakh has been received and kept in Subsidy Reserve Fund A/C of the borrower/Promoter on which no interest is charged. 2. A Sign Board has been exhibited at the project site indicating that the project has been 'Assisted under sub scheme Agricultural Marketing Infrastructure of Integrated Scheme for Agricultural Marketing (ISAM) of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India'. 3. Certificate by the FI that all original bills, vouchers etc. are preserved for any verification in future. 	
JM-3	Completion certificate by approved engineer / registered architect. It should be signed by the promoter and countersigned by Branch Manager of FI.	
JM-4	In case of storage infrastructure: Certificate issued by the approved engineer / registered architect that the project has been completed as per the technical specifications specified in guidelines.	
JM-5	Certificate by Chartered Accountant indicating item-wise actual expenditure countersigned by Branch Manager of FI.	

**FORMAT FOR CLAIMING FINAL SUBSIDY
(TO BE SUBMITTED BY FINANCIAL INSTITUTION TO NABARD AND DMI)**

To,

- (1) Regional Office, NABARD
- (2) Regional Sub-office, Directorate of Marketing & Inspection
(Nearest as per addresses enclosed)

AGRICULTURAL MARKETING INFRASTRUCTURE

PART 6 I

(FOR USE BY FINANCIAL INSTITUTION)

1. (i) Name, full address / location of project with telephone number and email ID including Tehsil / Taluka / District :
- (ii) Whether located in North East Region/
States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir,
Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep Island /
Hilly Areas/ Tribal Areas :
2. (i) Name and full address of promoter with telephone number and email ID including Tehsil / Taluka / District :
- (ii) Whether belongs to Registered FPOs/, Women / SC/ ST/
their cooperatives :
if yes specify :
- (iii) Whether belongs to State Agencies :
- (iv) Whether proprietorship/ partnership :
a) If yes, rate of entitlement of subsidy (25% / 33.33%) :
3. Type of Infrastructure projects:
(Storage/Other than storage/Farmers Consumer Market/Development/Upgradation of Rural Haats/RPMs into GrAMs)
4. Rate of entitlement of subsidy for projects (25% / 33.33%) :
5. Name and address of financing financial institution with telephone number and email ID :
a) Account No. and IFSC code of FI :
b) AADHAR no of Promoter :
6. Date of sanction of term loan by financial institution :
(a) Amount of loan sanctioned :
(b) Date of disbursement of first instalment :
(c) Date of disbursement of the last instalment :
(e) Total Loan amount disbursed :
(enclose the loan account statement showing details of amount released)

7. Date of completion of the project :
- a) Date of submission of Completion certificate :
- b) Date of submission of item wise actual expenditure certificate :
- Date of completion (last of a & b) :
8. Date of last inspection of project by financial institution :

9. Item wise cost of project

	As per project report (Rs.)	As approved by FI (Rs.)	Actual expenditure incurred (Rs).
i) Marketing Infrastructure/ Storage Infrastructure			
ii) Allied facilities / infrastructure / Plant & Machinery			
a)			
b)			
iii) Cost of civil structure			
iv) Project Cost for processing			
a) Cost relating to primary processing			
b) Cost relating to secondary & other processing			
Total outlay			

10. Means of finance:

	As per project report (Rs.)	As approved by FI (Rs.)	Actual expenditure incurred (Rs).
Promoter's contribution			
Term loan			
Total outlay			

11. Brief account of the infrastructure to be created

Under the project

- a) Description of components with cost :
- b) Storage Infrastructure capacity :
- | | | |
|-----------------|-------------------|----------|
| No. of chambers | Size | Capacity |
| | (LxBxH in Meters) | (in MT) |
- c) New unit to be created
- d) Existing unit, if any

12. Total entitlement of the Subsidy :

13. Advance subsidy

- i) Date of receipt :
- ii) Amount :

14. Subsidy from any other agency:

State Govt.:

Central Govt. (for other components, if any). :

15. Balance subsidy to be released :

16. Certified that the Infrastructure facility created is as per the technical specifications envisaged in the guidelines of the sub-scheme and the project proposal.

17. Certified that all the special conditions for storage infrastructure have been followed.

18. Certified that various permissions/approvals have been obtained by the promoters for establishment and commissioning of the project from various government authorities. FI has ensured that the project has all requisite permissions/approvals.

19. It is certified that no subsidy / grant has been or will be availed for the project from any other Central Government department/ agency including subsidy under RKVY/ MGNREGA.

20. Certified that the promoter has not availed or will avail maximum subsidy as explained under Para 9 of the operational guidelines.

21. Certified that the financial institution will ensure that the promoter will not alienate the land and the project for a minimum period of term loan for any purpose other than the purpose for which the subsidy is extended. We note that the subsidy under the scheme is back ended which cannot be adjusted before the minimum locking period of 5 years.

22. Since the above project is complete as per terms & conditions stipulated under the sub scheme, an amount of Rs. _____(Rupees_____) being the final instalment of subsidy may please be released for crediting to the Subsidy Reserve Fund Account Borrower wise.

23. It is certified that the observation(s) made by the Joint Inspection Committee if any, will be complied within 60 days of joint inspection.

[_____]

Seal and Signature of the Branch Manager
(Financial Institution)

Place:

Date:

Enclosures: Completion certificate, Item wise actual expenditure certificate, etc. as per the Annexure VIII

AGRICULTURAL MARKETING INFRASTRUCTURE**PROFORMA FOR JOINT INSPECTION REPORT**

Date of Inspection:

1. Members of Joint Inspection Committee:

Organization	Name of the Officer	Designation	Address
NABARD			
FI			
DMI			

2. i) Name and address of project with telephone No.
(including Village, Tehsil/ Taluka/ District) :

ii) Name & Address of the Promoter with telephone No.
and Email ID :

iii) Whether located in North East Region/ States of Uttarakhand,
Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir Andaman & Nicobar Islands
& Lakshadweep Island / Hilly Areas/ Tribal Areas :

iv. Type of Infrastructure projects:
(Storage/Other than storage/Farmers Consumer Market/Development/Upgradation of Rural
Haats/RPMs into GrAMs)

v) Category specify :

(a) Whether belongs to Registered FPOs/ Women/ SC/ST/ their Co-operatives :

(b) Individual :

(c) Company/Corporation :

(d) State agency :

(e) Others :

3. Whether proprietorship/ partnership :

4. Rate of Entitlement of subsidy (25% or 33.33%) :

5. Name and Address of the FI with telephone No. and Email ID :

6. Details of loan sanctioned

i. Date of receipt of proposal / application to the FI :

ii. Date of sanction of loan :

iii. Amount of loan sanctioned :

iv. Date & Amount of disbursement of first instalment :

v. Date & Amount of disbursement of last instalment :

vi. Total loan amount disbursed :

vii. Date of commencement of project :

viii. Date of Completion of Project & submission of documents :

ix. Whether completed & documents submitted in time :

If not, subsidy calculation based on date of completion & submission of documents

- a) Prescribed date of completion & submission of documents :
- b) Actual Date of completion & submission :
- c) Time period of delay (b-a) :
- d) Applicable deduction of subsidy _____ % & Amount: _____
- e) Final applicable subsidy _____ % & Amount: _____

xi. Date of intimation of completion & submission of documents of project for joint inspection to NABARD and DMI :

- 7. Details of sanctioned Project :
- i) Details of infrastructure created (in brief) :
- ii) Total Project cost :
- iii) Item-wise cost of project :

Sl. No.	Items	As per Project Report (Rs)	As appraised by FI (Rs)	Actual expenditure incurred (Rs.)	Expenditure verified by the JIC (Rs.)
1	Civil Work				
2	Plant and Machinery i) ii) iii)				
3	Allied / Ancillary facilities				
4	Others (Specify)				
	Total				

- iv) Project Cost for processing:
 - a) Cost relating to primary processing:
 - b) Cost relating to secondary & other processing:

8. Brief account of the infrastructure to be created

Under the project

- a) Description of components with cost :
- b) Storage Infrastructure capacity :

No. of chambers	Size	Capacity
	(LxBxH in Meters)	(in MT)
- c) New unit to be created
- d) Existing unit, if any

9. Means of finance :

	As per project report (Rs.)	As approved by FI (Rs.)	Actual expenditure incurred (Rs).	Expenditure verified by the JIC (Rs.)
Promoter's contribution				
Term Loan				
Total				

10. Whether project implemented as per approval (specifications etc.) :
If no, specify the deviations :

11. Total entitlement of Subsidy

a) Eligible project cost for calculation of subsidy :

b) Capacity in MT (to be filled in case of storage project):

c) Final subsidy recommended :

12. Date and Amount of Advance subsidy received :

13. Subsidy from any other agency :

a) State Govt. :

b) Central Govt. (for other components, if any) :

14 Balance subsidy to be released :

15. Any other observations/ deficiencies :

16. Recommendations of the Joint Inspection Committee :

Signature & date
NABARD

Signature & date
Financial Institution

Signature & date
DMI

Format for Utilization Certificate

(FOR THE USE OF FI TO BE SUBMITTED TO THE REGIONAL OFFICE OF NABARD)

AGRICULTURAL MARKETING INFRASTRUCTURE

1. Name, Project Code No., address and location of the promoter and project:
2. Name of the financial institution:
3. Name & address of the financing branch :
4. Branch IFSC Code:
5. Date of sanction of loan by financial institution:
6. Date of inspection by Joint Inspection Committee:
7. Date of commission of the unit:
8.

(i)	Total financial outlay	-Rs.	
(ii)	Promoter's contribution	-Rs.	
(iii)	Loan	-Rs.	
(iv)	Subsidy received	Date of receipt From NABARD	Amount (Rs.)

Date of credit to the Subsidy Reserve Fund A/c No. of the Borrower

 - a) Advance Subsidy
 - b) Final subsidy
9. Brief description of infrastructure created with capacity etc.:

10. This is to certify that the full amount of subsidy received in respect of the above project has been fully utilized (by way of crediting to the Subsidy Reserve Fund Account-borrower-wise) to be adjusted in the books of account under the sanctioned terms and conditions of the project within the overall guidelines of the sub scheme after the lock-in period of 5 years.

Place

Date

Seal & Signature of the
Authorized Signatory of Financial Institution

**FORMAT FOR CLAIMING FIRST INSTALLMENT OF SUBSIDY FOR OWN FUNDED
STATE AGENCY PROJECTS**

(to be submitted by the State Agency to DMI, HO, Faridabad through RO/SO after sanctioning of the Project by the Project Sanctioning Committee of D.M.I./D.A.C & FW)

To

The Agricultural Marketing Adviser
to the Govt. of India
Directorate of Marketing & Inspection
Head Office, N.H.IV
Faridabad-121001.

SUB – SCHEME OF AGRICULTURAL MARKETING INFRASTRUCTURE

1.	Name & address of the State agency									
2.	Name & address of the project									
3.	Whether located in North Eastern Region/ States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep Island/ Hilly Areas/ Tribal Areas									
4.	Name & address of the controlling authority									
5.	Date of submission of proposal/application to DMI									
6.	Type of Infrastructure projects: (Storage/Other than storage/Farmers Consumer Market/Development/Upgradation of Rural Haats/RPMs into GrAMs)									
7.	Total project cost as submitted by the State agency (Rs. in lakh)									
8.	Amount of State agency contribution for the project (Rs. in lakh)									
9.	Rate of entitlement of subsidy 25% or 33.33%									
10.	Brief coverage on Technical feasibility (enclosure)									
11.	Other information on whether various permission/approval obtained by the State agency for establishment and commissioning of the project from various Govt. authorities									
12.	Brief account on the infrastructure of the project to be created (enclosure)									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Item</th> <th>Cost</th> <th>Subsidy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Sl. No.	Item	Cost	Subsidy					
Sl. No.	Item	Cost	Subsidy							
13.	An amount of Rs. í í í í í .. (Rupees í í í í í í í í í .) being the 50% of the eligible amount of subsidy may please be released in respect of the project									

Place:

Date:

Enclosures: As above.

Signature:

Name:

Address:

**FORMAT FOR CLAIMING FINAL SUBSIDY FOR OWN FUNDED STATE AGENCY
PROJECTS**

(to be submitted by the State Agency to DMI, H.O. Faridabad)

To,

The Agricultural Marketing Adviser
to the Govt. of India,
Directorate of Marketing & Inspection,
Head Office, N.H.IV,
Faridabad-121001.

AGRICULTURAL MARKETING INFRASTRUCTURE

1	Name & address of the State Agency	:
2	Name & address of the project	:
3	Name & address of the controlling authority	:
4	Date of sanction of project by the Sanctioning Committee	:
	5. Type of Infrastructure projects: (Storage/Other than storage/Farmers Consumer Market/Development/Upgradation of Rural Haats/RPMs into GrAMs)	
6.	Total cost of the project as approved by the Sanctioning Committee(Component-wise):	Rs.
7.	State Agency contribution	Rs.
8	Total eligible subsidy as approved by the Sanctioning Committee	Rs.
9	Amount of first installment of subsidy and date of receipt	Rs.
10	Brief account of the item-wise progress of works undertaken so far under the project (duly certified by a Competent Engineer of the State Agency or that of State Government)	:
11	Total amount of expenditure incurred so far in the project ó Component-wise details, duly certified by a Chartered Accountant	Rs.
12	Amount of final subsidy claimed (Rs.)	

Sr. No.	Item	Cost as per proposal	Cost appraised by Appraisal Agency	Cost Sanctioned by Sanctioning Committee	Actual Expenditure	Eligible Subsidy	Advance Subsidy Received	Balance final Subsidy

13. Certified that above project is nearing completion as per terms, conditions stipulated under the sub scheme and we have fully utilized both our contribution for the project as well as advance subsidy received and that the project requires only an amount equivalent to the second installment of subsidy from the Central Government for its completion. Utilization Certificate for the first installment of subsidy is enclosed as per prescribed format GFR 12-A.

14. It is requested that an amount of Rs. _____ (Rupees _____) being the second installment of subsidy may please be released for completing the project. The Utilization Certificate for second installment of subsidy will be submitted immediately after completion of the project as per time period prescribed under the sub scheme.

15. It is certified that no subsidy / grant has been availed or will be availed for the project from any other Central Government Department/ Agency including RKVY/ MGNREGA.

Place:

Signature:

Date:

Name:

Address:

Enclosures: As above.

**PROFORMA FOR INSPECTION OF OWN FUNDED STATE AGENCY PROJECTS UNDER
AMI**

1. Members of Joint Inspection Committee:

Date of Inspection:

Organization	Name of the Officer	Designation	Address
DMI			
State Agri. Marketing Board/ State Agency			

1.	Name & Address of the State agency	
2.	Name & Address of the State agency project	
3.	Whether located in North East Region/ States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep Island / Hilly Areas/ Tribal Areas	
4.	Name & Address of Controlling authority of the State agency	
5.	Date of Sanction of the project by the Sanctioning Committee	
6.	Type of Infrastructure projects: (Storage/Other than storage/Farmers Consumer Market/Development/Upgradation of Rural Haats/RPMs into GrAMs)	
7.	Total cost of project as approved by Sanctioning Committee (Rs. in lakhs)	
8.	Amount of State Agency contribution (Rs. in lakhs)	
9.	Total eligible subsidy approved by the Sanctioning Committee (Rs. in lakhs)	
10	Date & Amount of release of first installment of subsidy by DMI	
11	Date of Commencement of Project	
12	Brief account of the item-wise progress of the works undertaken so far under the project by indicating following points (Duly certified by a competent Engineer of the State agency or that of State Govt.) (enclosure). i)Project Item (Component) : ii) Cost iii)Extent up to which completed : iv)Reasons for pending works (if any): v)Whether Construction is as per specifications envisaged in the guidelines and approved project report	
13	Total amount of expenditure incurred so far in the project item-wise details, duly certified by the CA by indicating following points (enclosure) i) Project Item (Component) ii) Expenditure Incurred	

14	Balance subsidy to be released								
	Sr. No	Item	Cost as per proposal	Cost appraised by Appraisal Agency	Cost Sanctioned by Sanctioning Committee	Actual Expenditure	Eligible Subsidy	Advance Subsidy Received	Balance final Subsidy
15	Observations / Recommendations (The Inspecting Officers should specify about dropping of component during construction and change of TFO, if any)								

Signature & date
DMI

Signature & date
State Agency

**On non-judicial stamp paper of Rs. 100/-
Affidavit**

I/we í í í í í í .. S/o í í í í í í í í Resident of
í director / proprietor of M/s
í í í í í í í í í í í í í í í í í í . do here by solemnly affirms and state that:

1. I / we have not availed or will avail grant/subsidy for the project proposal submitted under sub scheme Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) of Integrated Scheme for Agricultural Marketing (ISAM) of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare from any other Central Government scheme including Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)/MGNREGA.
2. I / we will obtain all the requisite permissions / approvals from the concerned authorities to build and operate the project as per applicable laws.
3. I / we will not alienate the land and the project for a minimum period of term loan for any purpose other than the purpose for which the subsidy is extended.
4. I / we will be liable to refund the subsidy of the project or its component that is dropped / cancelled or if any change is made in any of the components of the project sanctioned.
5. I / we will submit all the requisite documents after completion within the stipulated time period and agree to the penalty for delay in submission as per the sub scheme AMI guidelines.
6. I / we will not close the loan account for a minimum period of 5 years from the date of disbursement of first instalment of loan. In case of pre closure of loan account, I / we will forfeit the benefit of subsidy.
7. I / we agree that subsidy under the scheme is not guaranteed and is not a matter of right. I / we agree that subsidy is subject to availability of funds and receiving of proposals at NABARD at first come first serve basis in addition to the compliance of scheme guidelines as may be interpreted and altered by GoI with/ without notice.

I / we hereby solemnly affirm and state that I / we will be liable to forfeit / refund the subsidy for non compliance of above.

Deponent

Verification:

Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed therein, If anything is found false in this Affidavit subsequently deponent will be liable jointly and severally for action under the laws, hence verified at _____(Place) on _____(Date).

Deponent

Notary Sea l& Signature

ANNEXURE – XIX

A: Progress of sub Scheme AMI

Month:

Amount (Rs. in lakhs)

Sr. No.	State	Category of projects	No. of Projects	Capacity (in MT)	TFO	Term loan	Promoter's contribution	Eligible Subsidy	Subsidy Released				Remarks
									Advance	Final	One time	Total	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1		Storage											
		Silos											
		Infrastructure Other than storage											
		Farmers Consumer Markets											
		Development/Upgradation of Rural Haats/RPMs into GrAMs											

	STATUS OF SUBSIDY RELEASE	Amount (Rs. in lakhs)
A	OPENING BALANCE OF FUNDS AS ON 01.4.20.... (current year)	
B	FUNDS RECEIVED FROM DAC&FW DURING CURRENT YEAR	
C	TOTAL FUNDS AVAILABLE AS ON (A+B)	
D	TOTAL SUBSIDY RELEASED UP TO (Current Year - TOTAL)	
	Of WHICH, ADVANCE SUBSIDY	
	FINAL SUBSIDY	
	ONE TIME SUBSIDY	
E	BALANCE OF FUNDS AVAILABLE UPTO THE MONTH ending (C-D)	

B: State-wise Progress of sub Scheme AMI

Name of the State:-

Month:

Amount (Rs. in lakhs)

S. No.	Category of project	Project Sanctioned during the Current Year up to the Month			Cumulative Projects Sanctioned up to the Month beyond XII Plan											
		No. of Projects Sanctioned	TFO	Total Eligible Subsidy	Total No. of Projects Sanctioned	TFO	Total Eligible Subsidy	Projects Completed*				Projects to be completed				
								No.	TFO	Subsidy Released		No.	TFO	Advance Subsidy Released	Subsidy to be Released	
										Advance	Final				Advance	Final
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1	Primary Processing and Value Addition Facility Cleaning, Grading, Storage and Packaging Unit															
2	Direct Marketing & E trading projects															
3	Pre-cooling/Cold chain facility															
4	Common Facility in Market															
5	Mobile Infrastructure															
6	IVC															
7.	Farmers Consumer Markets															
8.	Development/Upgradation of Rural Haats/RPMs into GrAMs															
9.	Storage Infrastructure	Silos No: Capacity: (MT)			Silos No: Capacity: (MT)			Silos No: Capacity: (MT)				Silos No: Capacity: (MT)				
		Other No: Capacity: (MT)			Other No: Capacity: (MT)			Other No: Capacity: (MT)				Other No: Capacity: (MT)				
Total:																

* Projects completed refer to projects where final subsidy is sanctioned or released.

C: PROFORMA FOR SUBMISSION OF LIST OF SANCTIONED PROJECTS UNDER THE SUB SCHEME AMI

State :

Year:

Sl. No.	Code No.	Name & Address of the promoter with Phone Number	Name of the project & Address (Location)	District	Constitution of firm (Individual/NGO/Co. etc.)	Male / Female / Other (Partnership firms, companies etc.)	SC / ST/ Other	NE/Hilly/Tribal/Other Area	Category of Project / Infrastructure	Type of Project / Infrastructure	Name & Address of FI	Date of receipt of the project by the FI	Date of sanction of term loan	Date of Disbursement of 1st Instalment of loan	TFO as appraised by FI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															

Amount of Loan	Promoters contribution	Date of submission of project Profile-cum-claim form for advance subsidy by FI to NABARD	Rate of Subsidy (25% or 33.33%)	Total eligible subsidy	Date of sanction of Advance subsidy	Date of release of Advance subsidy	Amount of release of Advance subsidy	Date of completion of Project	Date of Joint Inspection	Date of sanction of Final Subsidy	Date of release of Final Subsidy	Amount of release of Final Subsidy	Total Subsidy Released	In case of Storage Capacity (MT),	Remarks*
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

* Please furnish the other relevant information in remarks column.

D: PROFORMA FOR SUBMISSION OF QUARTERLY FINANCIAL PROGRESS REPORT UNDER THE SUB SCHEME AMI

Progress report at the end of the quarter -----

Year -----

(Rs.- in Lakhs)

Implementing agency	Unspent balance of grants-in-aid as on 1 st April of the current year	Grants-in-aid released so far during the current quarter	Funds utilized so far towards subsidy during the current quarter	Unspent balance of grants-in-aid available by the end of quarter	Anticipated demand for the next quarter	Remarks